चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 11 जुलाई– 17 जुलाई 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अखिलेश जी !

सात हज़ार करोड़ कहां हैं ?

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार के सात हजार करोड़ रुपये हिसाब से गायब

राजस्व को साढ़े चार सौ करोड़ का सालाना नुकसान अलग से

ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन व निर्माण निगम की साठगांठ उजागर

काम के पहले ही निर्माण निगम को दे दिए एक हजार करोड़

घटिया और अधोक्षमता वाले सब-स्टेशनों का फैला दिया जाल

भ्रष्ट अफसरों को दी गई तरक्की और मनचाही तैनातियां

उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने का सात हजार करोड़ रुपया गायब है. सात हजार करोड़ रुपये का हिसाब ही नहीं मिल रहा है. उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के शीर्ष पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने साठगांठ करके ऊर्जा मद की इतनी बड़ी धनराशि का गड़बड़झाला कर दिया है. इस घोटाले से प्रदेश सरकार को 450 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है. नुकसान की राशि घोटाले की राशि से अलग है. हजारों करोड़ रुपये का घपला करने वाले राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक आरएन यादव को सफलतापूर्वक भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार ने पुरस्कृत किया और उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के योजना महकमे का निदेशक बना दिया गया. आरएन यादव की 'विशेषज्ञता' की साख यह है कि सरकार ने उन्हें पावर कॉरपोरेशन के कार्मिक महकमे के निदेशक का भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा है. यह मामला अगर निष्पक्ष जांच की तरफ जाए तो भ्रष्ट-पुरुष यादव सिंह प्रकरण से भी बड़ा घोटाला साबित हो. फर्क केवल इतना रहेगा कि एक का नाम यादव है और दूसरे का उपनाम यादव है. पूरा सिस्टम ऐसे लोगों पर कितना मेहरबान रहता है, उसका उदाहरण है कि जिस समय इस घोटाले की पटकथा लिखी गई उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक रहे एसके अग्रवाल को बाद में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का सदस्य बना कर महिमामंडित कर दिया गया. उस समय ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के मुख्य महाप्रबंधक रहे एके अग्रवाल को रिटायर होने के बाद कॉरपोरेशन का सलाहकार नियुक्त कर लिया गया. अग्रवाल ने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी खोल रखी है. ये सब भ्रष्टाचार करने में भी सलाहकार थे और अब भ्रष्टाचार की जांच में भी सलाहकार रहेंगे. इसी प्रायोजित-प्रक्रिया से देश से भ्रष्टाचार जाएगा. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम मायावती के शासनकाल में भी अरबों रुपये के स्मारक-स्थापत्य घोटाले में काफी नाम कमा चुका है. मायावती सरकार के उस अरबों रुपये के घोटाले पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब मायावती की सरकार आएगी तो वह सपा सरकार के घपले-घोटाले पचा जाएगी. भ्रष्टाचार में मायावती-अखिलेश में बेहतरीन समझदारी है.

प्रदेशभर में तकरीबन 80 विद्युत सब-स्टेशनों (उप-केंद्रों) के निर्माण के लिए जो धनराशि दी गई थी, उसमें भीषण भ्रष्टाचार किया गया है. इसमें केंद्र सरकार से करीब 20 हजार करोड़ रुपये यूपी के लिए आवंटित हुए. कानूनी प्रावधान है कि विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए उसी संस्था को ठेका दिया जाएगा, जिसे विशेषज्ञता और अनुभव हासिल हो. लेकिन पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अलमबरदारों ने इस क्षेत्र में गैर-अनुभवी और गैर-विशेषज्ञ संस्था राजकीय निर्माण निगम को 51 विद्युत सब-स्टेशन बनाने का बड़ा ठेका दे दिया. विद्युत सब-स्टेशन बनाने के लिए राजकीय निर्माण निगम की ओर से कोई योजना-प्रस्ताव, बजट-आकलन और निर्माण की तैयारियों का अग्रिम ब्यौरा भी नहीं दिया गया, लेकिन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के निदेशक (ऑपरेशंस) आरएस पांडेय की तरफ से आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया. निर्माण निगम के नाम से 220 केवी का 21 सब-स्टेशन बनाने और 132 केवी का 30 सब-स्टेशन बनाने की लॉटरी खोल दी गई. निर्माण निगम को ठेका देने में सारे प्रावधान ताक पर रख दिए गए और काम शुरू करने के पहले ही एक हजार करोड़ रुपये का एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया. एक हजार करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करने की इतनी हड़बड़ी थी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने सीधे अपने ही फंड से निर्माण निगम को पेमेंट जारी कर दिया. इस पेमेंट के बारे में डिवीजन को कुछ पता ही नहीं चला, जबकि सारे भुगतान सम्बद्ध डिवीजन के जरिए ही होने चाहिए. बाकी बचे सब-स्टेशनों को बनाने का ठेका लार्सन एंड टूब्रो, क्रॉम्पटन ग्रीव्ज़ व कुछ अन्य नामी कंपनियों को दिया गया. इन कंपनियों ने बाकायदा सारी औपचारिकताएं पूरी कीं, योजना-प्रस्ताव दिया, अपना बजट-आकलन पेश किया और सब-स्टेशनों के निर्माण में लगने वाली सामग्री और उपकरणों का अग्रिम ब्यौरा भी प्रस्तुत किया. इन कंपनियों को कोई एडवांस भी नहीं दिया गया. प्रदेशभर में विद्युत सब-स्टेशन बन गए, लेकिन निर्माण के दरम्यान कभी उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ और सामान व उपकरणों की गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हुई.

सारे विद्युत सब-स्टेशन बन गए और मुख्यमंत्री ने फीता काट कर उसे शुरू भी करा दिया. राजकीय निर्माण निगम समेत अन्य निर्माता कंपनियों का भुगतान भी हो गया. लेकिन करीब सात हजार करोड़ रुपया हिसाब से गायब है. उसका कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है. दस्तावेज बताते हैं कि 6972.35 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है. कॉरपोरेशन ने सात हजार करोड़ रुपये में से 5921.88 करोड़ रुपये रूरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (आरईसी) और पावर फिनांस कॉरपोरेशन (पीएफसी) से 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में लिए थे. ब्याज को देखते हुए साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का जो नुकसान हो रहा है, वह घोटाले की राशि से अलग है. आराजकता का हाल यह है कि सब-स्टेशनों के निर्माण के बाद राजकीय निर्माण निगम ने खर्चे का ब्यौरा (कैपिटलाइजेशन) प्रस्तुत करने की कोई जरूरत ही नहीं समझी. जबकि यह कानूनी अनिवार्यता है. निर्माण निगम ने बिजली घरों के निर्माण के बाद उसे हैंडओवर करने के समय न कोई सामान बचा हुआ दिखाया और जो उपकरण लगे उसका भी कोई विवरण (टेक्निकल स्पेसिफिकेशन) नहीं दिया. हैरत की बात यह है कि कई 'मान-मनुहार' के बाद निर्माण निगम ने महज छह बिजली घरों के निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत किया वह भी सिर्फ एक पन्ने में. ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने इस एक पन्ने के पूंजीकरण को भी बिना उसे जांचे-परखे पास कर दिया. भद्दा मजाक यह है कि कॉरपोरेशन ने उस एक पन्ने के ब्यौरे पर लिखा कि निर्माण निगम खुद ही अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट से इसकी जांच करा ले. निर्माण निगम द्वारा बनाए गए सब-स्टेशन अब असली औकात पर आ रहे हैं. जो ट्रांसफर्मर लगाए गए, वह कम क्षमता वाले निकल रहे हैं. उस पर भी इंजीनियरों पर दबाव दिया जा रहा है कि वे क्लीन-चिट दे दें.

सात हजार करोड़ के इस विशाल घोटाले को तकनीकी तौर पर भी देखते चलें. वर्ष 2015-16 का पारेषण (ट्रांसमिशन) टैरिफ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 18.06.2015 को जारी किया गया था. आयोग ने ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता में संभावित पूंजीकरण व्यय का 30 प्रतिशत काट कर पारेषण टैरिफ निर्धारित किया तथा इस गंभीर प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए जरूरी निर्देश दिए थे. कटौती का कारण यह था कि ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का एसेट रजिस्टर आधा-अधूरा पाया गया था. इस सम्बन्ध में निदेशक (वाणिज्य) के पत्र (संख्या-265, दिनांक 27.07.2015 और संख्या-269, दिनांक 29.07.2015) द्वारा निदेशक (वित्त) से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया. कॉरपोरेशन के एसेट रजिस्टर को आधा-अधूरा बताए जाने की असली वजह यह थी कि ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन (पारेषण निगम) के नाम पर तकरीबन सात हजार करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था. उक्त धनराशि में से अधिकांशत: पीएफसी और आरईसी से 12 प्रतिशत के ब्याज पर कर्ज के रूप में ली गई है.

नवम्बर 2015 और उसके बाद की सभी समीक्षा बैठकों में इस तथ्य को उठाया गया और साथ ही इतनी बड़ी लंबित धनराशि का हिसाब जानने के लिए फील्ड इंजीनियरों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया. वाणिज्य अनुभाग के निरंतर प्रयास से उक्त धनराशि के लंबित प्रकरणों को हल करते हुए बहुत मुश्किल से 15 सौ करोड़ रुपये की राशि के खर्च का हिसाब-किताब (पूंजीकरण) जुटाया जा सका, लेकिन शेष धनराशि का हिसाब नहीं मिल रहा. इतना ही बताया जा रहा है कि 6972.35 करोड़ रुपये पाइपलाइन में हैं. इसमें 2099.40 करोड़ रुपये कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस (सीडब्लूआईपी) में, 3822.48 रुपये कैपिटल एडवांस में और 1050.47 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं. यह आंकड़ों की आधिकारिक बाजीगरी है, आम शब्दों में जिसे हेराफेरी कहते हैं. इसी महकमे के एक आला अधिकारी से जब पाइप लाइन के सोत से लेकर निकासी के बारे में पूछा तो वे सोत तो बता पाए, पर निकासी के बारे में गोलमोल कर गए. उपरोक्त धनराशि में 5921.88 करोड़ रुपया वित्तीय संस्थाओं (पीएफसी व आरईसी) से 12 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया कर्ज है. इस ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए पूंजीगत व्यय का पूंजीकरण कर उसे वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है. लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा.

पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक (एमडी) विशाल चौहान को इस मामले की सारी जानकारी औपचारिक तौर पर 14.03.2016 को दे दी गई थी. इस जानकारी में यह तथ्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अरबों के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया से अभियंताओं को अलग रखा गया. जबकि टेंडरों के निर्धारण से लेकर विद्युत सब-स्टेशनों के निर्माण और उसकी गुणवत्ता की गहन जांच के लिए बाकायदा लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद और मेरठ में चार विद्युत मंडल बनाए गए थे और उसे आठ खंडों में विभाजित कर तमाम अभियंताओं की तैनाती की गई थी. इस औपचारिकता में ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को अलग से 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. इसके अलावा भी तमाम सरकारी तामझाम किए गए थे. लेकिन कॉरपोरेशन के शीर्ष अधिकारियों के निर्देश पर निदेशक और डिजाइन एंड प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंताओं ने फील्ड इंजीनियरों को काम करने से रोक दिया था. इतनी अवधि तक सारे अभियंता बगैर काम के ही अपना वेतन उठाते रहे, सरकारी खजाने का यह नुकसान अलग से हुआ. यह भी भेद खुला है कि उत्तर प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने सब-स्टेशनों के निर्माण का ठेका राजकीय निर्माण निगम को दिया, लेकिन निर्माण निगम ने उसे ऊंची कीमतों पर दूसरे प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया. यानी, निर्माण निगम ने सब-स्टेशनों के निर्माण में दो तरफा कमाई की. एक तरफ उसने सरकारी दर पर ठेका लिया और दूसरी तरफ ऊंची दर पर दूसरे ठेकेदारों को सब-लेट कर दिया. ठेकेदारों ने सारे घटिया सामान और उपकरण लगा कर सब-स्टेशन बना डाले. अब वही सब-स्टेशन निर्धारित क्षमता से कम के पाए जा रहे हैं.

अखिलेश जी! सात हज़ार करोड़ कहां हैं?

पृष्ठ 1 का शेष

शामिल था कि निजी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए अधिकांश कार्यों का पूंजीकरण कर दिया गया है, जबकि सरकारी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अब तक अपना कोई हिसाब नहीं दिया है और निगम के मद में पूंजीकरण की जरूरी औपचारिकताएं बाकी हैं. उक्त समीक्षा बैठक में सभी निदेशक मौजूद थे और बाकायदा उन सबके हस्ताक्षर से एक कार्यवृत्त (संख्या- 139, दिनांक- 17.03.2016) भी जारी किया गया.

कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा जो 30 (132 केवी) और 21 (220 केवी) मिला कर 51 सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया, उसके लिए मुख्यालय स्तर से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि राजकीय निर्माण निगम के खाते में सीधे स्थानांतरित की गई थी. उपरोक्त कार्यों का पूंजीकरण कराने के लिए प्रत्येक मासिक बैठक के साथ-साथ समय-समय पर मुख्यालय पर होने वाली समीक्षा बैठकों में भी यह संवेदनशील मसला उठाया जाता रहा और संबंधित पारेषण अभियंताओं से सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता रहा, लेकिन पूंजीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई. सम्बन्धित मुख्य अभियंता की रिपोर्ट के मुताबिक राजकीय निर्माण निगम के पास मात्र छह सब-स्टेशनों के बारे में सूचना उपलब्ध है, वह भी एक ही पेज में. राजकीय निर्माण निगम से पूंजीकरण के लिए बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

इस मामले में रेखांकित करने वाला तथ्य यह भी है कि सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता कार्यालय से निर्माण निगम को एडवांस जारी नहीं किया गया था. सारे नियमों को ताक पर रखते हुए एक हजार करोड़ से अधिक की राशि सीधे केंद्रीय लेखा अनुभाग से जारी कर दी गई. यही वजह है कि इस मामले में कोई भी अधिकारी या इंजीनियर हाथ डालने से हिचक रहे हैं. लेखा अनुभाग से सीधे एडवांस की इतनी भारी राशि जारी कर दी गई, लेकिन निगम से जो काम कराना था उसका कोई मापन-अंकन किया ही नहीं गया, जबकि वह नियमानुसार अत्यंत आवश्यक था. लेखा मुख्यालय के उप मुख्य लेखा अधिकारी का कहना है कि उक्त सभी भुगतान परिकल्प अनुभाग के आदेशानुसार किए गए. कार्यों का कोई विवरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है. फील्ड अभियंताओं का कहना है कि फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंताओं को किसी प्रकार के कार्यादेश और उसके भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उनके द्वारा केवल भौतिक प्रगति की सूचना प्रेषित की जाती थी, वह भी प्रतिशत में. विडंबना यह है कि खंडों में तैनात किए गए अभियंताओं को सब-स्टेशनों के निर्माण के दौरान सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के प्राथमिक दायित्व से ही अलग रखा गया और निर्माण निगम को मनमाने तरीके से काम करने की आधिकारिक छूट प्रदान की गई. अब उन्हीं इंजीनियरों पर निर्माण निगम के हिसाब-किताब को क्लीन-चिट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. सब-स्टेशनों का निर्माण हो जाने और बाकायदा काम शुरू होने के बाद पाया जा रहा है कि सब-स्टेशनों के निर्माण में घटिया सामान लगाए गए, निम्नस्तरीय विद्युत उपकरण लगाए गए और यहां तक निर्धारित क्षमता से कम के ट्रांसफर्मर भी लगा दिए गए.

राजकीय निर्माण निगम से हिसाब (पूंजीकरण) मांगा जा रहा है तो टालमटोल किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के शीर्ष अधिकारी इस मसले से कन्नी काट रहे हैं. स्पष्ट है कि मामला पूरी तरह संदिग्ध है. विभागीय नियमानुसार कोई भी कार्य कराने के लिए निविदा दरों का विश्लेषण कर न्यूनतम दर पर कार्य कराने का फाइनल आदेश जारी किया जाता है और सम्बन्धित कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए औपचारिक रूप से जिम्मेदारी आवंटित की जाती है, ताकि काम की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर दोषी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके. काम पूर्ण होने के बाद उसका मापन विभाग के अभियंता द्वारा किया जाता है और भुगतान के सम्बन्ध में गणना एवं कटौती लेखा शाखा द्वारा सुनिश्चित की जाती है. निर्माण निगम को जो काम दिया गया उसे देख कर यही लगता है कि राजकीय निर्माण निगम और सम्बन्धित ठेकेदार आवश्यक अभिलेखों में हेराफेरी या मैनिपुलेशन में लगे हैं, इसीलिए पूंजीकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है. घपला करने वाले अधिकारी मस्त हैं और उन्हीं अधिकारियों को तरक्की मिल रही है और उन्हें ही सरकार का संरक्षण भी मिल रहा है. ■

अखिलेश पचा गए मायावती के घोटाले

बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में पार्कों, मूर्तियों और स्मारकों की स्थापना के नाम पर अरबों के घोटाले किए गए थे. उस घोटाले में मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी लिप्त थे. 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मायावती के घोटालों को खास तौर पर रेखांकित किया और यह आश्वस्त किया था कि इन घोटालों की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी. सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने भी इस सिलसिले में कई बयान दिए, लेकिन ये सारे बयान फर्जी साबित हुए. स्मारक घोटाले में भी राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी लिप्त थे, लेकिन उस घोटाले में भी निर्माण निगम के भ्रष्ट अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ा. प्रदेश के तत्कालीन लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने पार्कों और स्मारकों के निर्माण घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट और दोषियों को सजा की सिफारिशों का दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंप दिया था. लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशों को अखिलेश यादव ने ठंडे बस्ते में डाल दिया. भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामलों पर अखिलेश की संवेदास्पद चुप्पी पर लोकायुक्त ने अपनी नाराजगी भी जताई थी. लेकिन इसका भी कोई असर अखिलेश पर नहीं पड़ा. यहां तक कि लोकायुक्त ने स्मारकों के निर्माण में 15 अरब रुपये के घोटाले के लिए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा सहित कुल 199 लोगों को दोषी ठहराते हुए उनसे रकम वसूलने की सिफारिश की थी और कहा था कि 19 लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. सपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया. लोकायुक्त ने 88 पन्ने की अपनी जांच रिपोर्ट में मायावती सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा से घोटाले की रकम का तीस-तीस फीसदी हिस्सा वसूलने की सिफारिश की थी. यह राशि 846 करोड़ रुपये होती. अभी ऊर्जा सेक्टर के एक महकमे में सात हजार करोड़ का घोटाला करने में शामिल निर्माण निगम और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के अधिकारियों से भी घोटाले की रकम वसूली जानी चाहिए. लेकिन घोटालों पर जब मुख्यमंत्री दम साधे बैठे हों तो कार्रवाई कैसे हो सकती है! मायावती काल में स्मारकों के निर्माण में राजकीय निर्माण निगम ने कुल 19,17,870.609 घनफुट सैंड स्टोन 50 रुपये प्रति घनफुट अधिक की कीमत बता कर खरीद दिखाई थी. इस तरह निर्माण निगम ने सैंड स्टोन की खरीद पर 9,58,93,530 रुपये का अधिक भुगतान ले लिया, जो कुल भुगतान का लगभग 34 प्रतिशत था. यानी, राजकीय निर्माण निगम ने मिर्जापुर सैंड स्टोन की खरीद में 34 प्रतिशत सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की केवल रस्म अदायगी दिखाई गई. निर्माण निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सीपी सिंह, अपर परियोजना प्रबंधक राकेश चंद्रा, एके सक्सेना, इकाई प्रभारी केआर सिंह, एसपी सिंह, एसके शुक्ला, मुरली मनोहर, सहायक स्थानीय अभियंता राजीव गर्ग, परियोजना प्रबंधक एसपी गुप्ता, पीके जैन, एसके अग्रवाल, आरके सिंह, बीडी त्रिपाठी, अपर परियोजना प्रबंधक मुकेश कुमार, हीरा लाल और एसके चौबे के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन लोकायुक्त की सिफारिशें नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित हुईं, फिर आम आदमी की बोली क्या बला है! भ्रष्टाचार का तो जोर इतना है कि यूपी के पड़ोसी राज्य में जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सीपी सिंह को सलाहकार नियुक्त कर लिया था.

निर्माण निगम पर अखिलेश हमेशा रहते नर्म

राजकीय निर्माण निगम बड़े-बड़े घोटालों में लिप्त रहा है, लेकिन निगम पर मुख्यमंत्री की कृपा रही है और निगम के भ्रष्ट अधिकारी फलते-फूलते रहे हैं. विधानसभा के सामने बन रहे सचिवालय और दारुलशफा परिसर के लिए राजकीय निर्माण निगम ने फिर मिर्जापुर सैंड स्टोन का घपला किया. इसमें निगम के एमडी आरके गोयल का नाम आया. आरके गोयल मायावती के भी चहेते रहे हैं, सत्ता बदलते ही वे अखिलेश के भी चहेते हो गए. गोयल ने सपाई कार्यकाल में भी बसपाई ठेकेदारों को खूब लाभ कमवाया और खुद भी मोटी कमाई की. इस पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने कानूनी आपत्तियां भी दर्ज कराईं और लोकायुक्त से शिकायत भी की. लेकिन जब लोकायुक्त की सिफारिशों को अखिलेश ने अंगूठा दिखा दिया तो नूतन ठाकुर की क्या बिसात है! निर्माणाधीन सचिवालय एनेक्सी हादसे में कई मजदूरों के मारे जाने के मामले में भी गोयल पर कोई सरकारी सख्ती नहीं हुई.

निर्माण निगम की अराजकता के कारण लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना का समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता की स्वप्न-परियोजना पर भी ध्यान नहीं दिया. मुलायम ने वर्ष 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद ही लखनऊ में कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया था. इसके लिए लखनऊ के चक गंजरिया फार्म को उजाड़ भी दिया गया और मुलायम ने शिलान्यास भी कर दिया, लेकिन सात सौ करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट आज तक खड़ा नहीं हो पाया.

राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने बन रहे सचिवालय एनेक्सी में हुए हादसे में मजदूरों के मारे जाने के बाद भीषण अफरातफरी मची, लेकिन सरकार और निर्माण निगम की संवेदनशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ा... (इनसेट: राजकीय निर्माण निगम के एमडी आरके गोयल)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 19
11 जुलाई- 17 जुलाई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

जानवरों को मारने-भगाने के लिए सांसदों ने लिखे पत्र

नीलगाय के साथ हाथी बंदर, सुअर भी निशाने पर

शशि शेखर

इंसान और जानवर के बीच सहअस्तित्व के संबंध के साथ अपने दायरे भी हैं. जब तक इन दायरों का अतिक्रमण नहीं हुआ, तब तक इंसान और जानवर के बीच का प्राकृतिक संबंध भी बना रहा. लेकिन, जब इंसानों ने जानवरों के क्षेत्र का अतिक्रमण करना शुरू किया, तब जानवर भी इंसान के क्षेत्र में घुसते चले गए. इंसानी आबादी को लेकर शायद ही किसी ने यह थ्योरी दी हो कि बढ़ती जनसंख्या से होने वाले नुकसान के लिए इंसानों को मार देना चाहिए या उनका बधियाकरण कर देना चाहिए. लेकिन, जानवरों की बढ़ती आबादी और इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए मौजूदा वन एवं पर्यावरण मंत्री समेत राज्य के कई मुख्यमंत्रियों और सांसदों को एकमात्र रास्ता यही समझ में आया कि इन जानवरों को मार दिया जाए या फिर इनका बधियाकरण कर दिया जाए. शायद तभी, पूरे देश में नीलगाय से लेकर मोर, जंगली सुअर, बंदर आदि को मारने के लिए बकायदा सरकारी अनुमति दी जाने लगी. बिहार में तो एक ही दिन में करीब 250 से अधिक नीलगायों को मार गिराया गया.

चौथी दुनिया के पास भाजपा सांसद हेमा मालिनी, अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, कम्युनिस्ट पार्टी की सांसद पीके श्रीमती, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वो पत्र मौजूद है, जिसमें इन लोगों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से अपने इलाकों में जंगली जानवरों को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बाड़बंदी कराने, हाथी और अन्य जंगली जानवरों से निपटने के लिए किसानों को आर्म्स लाइसेंस देने, जानवरों का

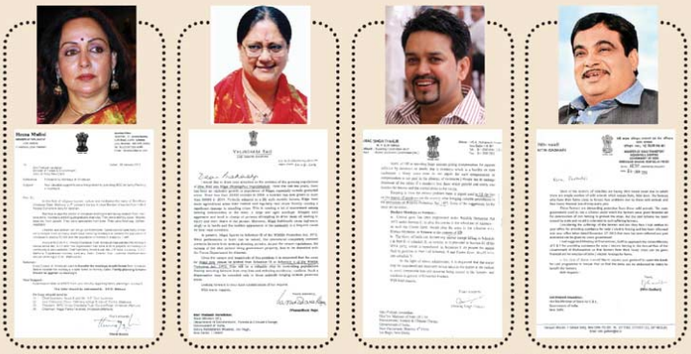

बधियाकरण करने आदि के लिए अनुरोध किया है. मसलन, अनुराग ठाकुर ने अपने पत्र में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में बंदरों के उत्पात से किसानों को मुक्त कराने के लिए इनके देश से बाहर निर्यात पर लगा रोक हटाया जाए. इसी तरह वसुंधरा राजे ने लिखा है कि राजस्थान में नीलगायों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शिड्यूल 2 से हटाकर शिड्यूल 5 में शामिल किया जाए. शिड्यूल 5 में शामिल करने का मतलब है कि इसका शिकार किया जा सकता है. वहीं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपने पत्र में प्रकाश जावडेकर से वृंदावन के बंदरों के बधियाकरण कराने की बात कही है. नितीन गडकरी ने विदर्भ में जंगली सुअर के आतंक से किसानों को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बाड़बंदी में सहायता देने का अनुरोध किया है, जबकि केरल के कन्नूर से सीपीआई सांसद पीके श्रीमती ने हाथियों और जंगली सुअर से बचाने के लिए किसानों को बंदूक के लाइसेंस देने का अनुरोध किया है.

गौरतलब है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसंबर 2015, 3 फरवरी 2016 और 24 मई 2016 को तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की थीं. इन अधिसूचनाओं के मुताबिक बिहार में नीलगाय, उत्तराखंड में जंगली सुअर और हिमाचल प्रदेश में बंदरों को एक साल के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाला घोषित किया गया था. यानी, इन्हें किसान मार सकते हैं. नीलगायों, बंदरों और जंगली सुअरों को हिंसक जानवर बताकर मारने के इस अधिसूचना के जारी होने के बाद इस मामले को एक गैर सरकारी संगठन सुप्रीम कोर्ट तक ले गया. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट गौरी मुलेखी और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की. इस याचिका में कहा गया है कि बिहार, हिमाचल और उत्तराखंड में नीलगाय, बंदर व जंगली सुअर आदि को मारना गलत है और इस पर रोक लगाया जाना चाहिए क्योंकि सरकार ने बिना किसी आधार और वैज्ञानिक अध्ययन के अधिसूचना जारी कर दी है. इस याचिका में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 62 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने अधिसूचनाएं जारी की हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि एक तो सरकार जंगलों में खनन नहीं रोक पाई है, जिसकी वजह से जानवर रिहायशी इलाकों में घुसने को मजबूर हुए हैं. इसके बाद उन्हें मारने का आदेश दिया जा रहा है, जो गलत है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना पर रोक लगाने से मना कर दिया है. हालांकि, अदालत ने इस शिकायत पर केंद्र सरकार से 14 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है. इसकी अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

वैसे बिहार में नीलगायों को मारे जाने को लेकर खुद मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो चुका है. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आरोप लगाती हैं कि पर्यावरण मंत्रालय हर राज्य को पत्र लिख रहा है कि बताओ किसको मारना है, हम इजाजत देंगे. दूसरी तरफ, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर का कहना है कि यह सब कानून के तहत किया जा रहा है. जब किसानों को फसल का नुकसान होता है और राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, तभी हम जानवरों को मारने की मंजूरी देते हैं. बहरहाल सवाल उठता है कि क्या फसल नुकसान से बचने का एकमात्र रास्ता इन जानवरों को मारना ही है? क्या सरकार को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि आखिर ये जानवर जंगल से खेतों की ओर या रिहायशी इलाकों की ओर क्यों आते हैं? हमने खुद जंगल और इन जानवरों के प्राकृतिक आवास को कितना नुकसान पहुंचाया है, क्या इस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत नहीं है? ■

feedback@chauthiduniya.com

महिला आरक्षण बिल

जारी है महिलाओं का इंतज़ार

शफीक आलम

संसद के मानसून सत्र में सरकार अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से लंबित पड़े विधेयकों को पास कराने की जी-तोड़ कोशिश करेगी. इन विधेयकों की भीड़ में एक ऐसा विधेयक भी है जो तकरीबन 20 साल से लंबित पड़ा है और पिछले कुछ वर्षों से उस पर चर्चा तक नहीं हुई है. यह विधेयक है देश की आधी आबादी को देश के नीति निर्धारण में प्रतिनिधित्व देने वाला महिला आरक्षण विधेयक या संविधान (108 वां संशोधन) विधेयक. इस विधेयक में लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई भागीदारी देने का प्रावधान है. एक-दो राजनीतिक दलों को छोड़कर देश के लगभग सभी दल इस बिल के समर्थन में हैं. हालांकि जो दल इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, वहां भी संदेह की दबी हुई आवाजें मौजूद हैं, जो गाहे-बगाहे मुखर हो उठती हैं. उदाहरण के लिए 2010 में राज्यसभा की मंज़ूरी के बाद जब इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, तब भाजपा के प्रभावशाली ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया था. नतीजा यह हुआ कि यह बिल ठंडे बस्ते में चला गया. यूं तो महिला सशक्तिकरण की बात सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की तरफ से होती है, सरकार घोषणाएं करती है, अलग से कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब कुछ कदम उठाने की बात होती है, तब हर तरफ सन्नाटा छा जाता है. राजनीतिक दलों के मामूली विरोध को बहाना बनाकर महिला सशक्तिकरण की कोशिशों को फाइल में बंद कर दिया जाता है और सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं.

लाल किला से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने की बात की थी. अपने दो साल के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण पर वे कई बार बोल चुके हैं. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कर चुके हैं. उनके मंत्रीमंडल में महिलाओं की ठीक-ठाक भागीदारी है, हालांकि वह एक-तिहाई नहीं. प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में भी महिला सशक्तिकरण की बात की थी, जिसने काफी हद तक महिला वोटरों को उनकी तरफ आकर्षित किया था, जिसका फायदा चुनाव में एनडीए को दो-तिहाई बहुमत के रूप में मिला था. ज़ाहिर है अगर वे देश की आधी आबादी की सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस काम उठाएंगे तो इसका चुनावी फायदा उनकी पार्टी को ज़रूर मिलेगा. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में महिला दिवस के मौके पर कहा था कि प्रधानमंत्री के मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना में महिलाओं का अधिकार भी आना चाहिए, इसलिए सरकार को महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द संसद से पारित कराना चाहिए. हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस ने मुकम्मल ख़ामोशी ओढ़ ली है.

महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन एचडी देवगौड़ा सरकार ने सदन में पेश किया था. विडंबना रही कि तब इस विधेयक के सबसे मुखर विरोधी मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, देवगौड़ा सरकार के प्रमुख स्तम्भों में से थे. लिहाज़ा यह बिल पास नहीं हो सका. वर्ष 1997 में एक बार फिर इसे पास करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी नतीजा शून्य रहा. 1998, 1999 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया, लेकिन हर बार यह हंगामों की भेंट चढ़ गया. इस दौरान यह महसूस किया गया कि बिल को समर्थन देने वाली पार्टियों के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस बिल को पास होते नहीं देखना चाहते.

2010 में भाजपा, वामदलों और जदयू के समर्थन से यूपीए सरकार ने राज्य सभा से इस बिल को पारित करा लिया, लेकिन लोक सभा में मामला तब फंस गया जब गोपीनाथ मुंडे व कुछ भाजपा सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ पार्टी में आवाज़ उठाई. तब से यह बिल आज तक धूल खा रहा है और किसी राजनीतिक दल में इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है. इसमें कोई शक नहीं कि संसद और विधान सभाओं में देश की महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी की तुलना में नहीं के बराबर है (देखें टेबल). जब महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो सका तो यह बात कही गई कि राजनीतिक दल अपने स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें. जब तक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित नहीं हो जाती हैं, तब तक सभी दल जो इस बिल के समर्थन में हैं, अपनी पार्टी की ओर से अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारें. लेकिन यह कवायद भी ज़बानी जमा खर्च साबित हुई (देखें टेबल). एक बार फिर यह साबित हुआ कि महिलाओं को लोकसभा और विधान सभा में उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के मामले में कोई भी दल गंभीर नहीं है.

बहरहाल, मौजूदा सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है. अगर वह चाहे तो इस बिल को संसद से भी पास कराकर राज्यों की मंज़ूरी के लिए भेज सकती है. या फिर समाजवादी पार्टी या दूसरे अन्य दल और खुद अपने सांसदों के संदेहों को दूर करने का प्रयास कर सकती है. जहां तक इस विधेयक का विरोध करने वाली पार्टियों का सवाल है तो अब उनकी संख्या लोकसभा में काफी सिमट गई है. लिहाज़ा सत्ता पक्ष की ओर से ऐसी पार्टियों के विरोध का बहाना अब नहीं चलेगा. लेकिन यदि यह बिल लोकसभा में पेश नहीं होता है या इस पर बहस नहीं होती है तो सरकार की नियत पर प्रश्न चिन्ह लगना लाज़मी है. एक बात तो तय है कि महिलाओं को अपना जायज़ हक हासिल करने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़नी होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

लोक सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

लोकसभा	सीटों की कुल संख्या (जहां चुनाव हुए)	विजयी महिलाओं की संख्या	महिलाओं का प्रतिनिधित्व (% में)
पहली (1952)	489	22	4.4
दूसरी (1957)	494	27	5.4
तीसरी (1962)	494	34	6.7
चौथी (1967)	523	31	5.9
पांचवीं (1971)	521	22	4.2
छठी (1977)	544	19	3.4
सातवीं (1980)	544	28	5.1
आठवीं (1984)	544	44	8.1
नवीं (1989)	529	28	5.3
दसवीं (1991)	509	36	7.0
ग्यारहवीं (1996)	541	40	7.4
बारहवीं (1998)	545	44	8.0
तेरहवीं (1999)	543	48	8.8
चौदहवीं (2004)	543	45	8.1
पंद्रहवीं (2009)	543	59	10.9
सोलहवीं (2014)	543	61	11.2

तीन लोक सभा चुनावों में राजनीतिक दलों की महिला उम्मीदवार

राजनीतिक दल	2004		2009		2014	
	उम्मीदवार	जीते	उम्मीदवार	जीते	उम्मीदवार	जीते
संपूर्ण भारत	355	45	556	59	668	61
कांग्रेस	45	12	43	23	57	4
भाजपा	30	10	44	13	37	28
अन्य	280	23	469	23	574	29

ऐसे समझौते का क्या मतलब!

एस. बिजेन सिंह

हाल में एक खबर सोशल मीडिया पर छाई रही कि केंद्र सरकार और नगा विद्रोही गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-आईएम) के बीच एक समझौता हुआ है. इसके तहत केंद्र सरकार ने नगालैंड के लिए अलग झंडा और अलग पासपोर्ट की मांग स्वीकार कर ली है. पूर्वोत्तर से इतर देश की मुख्य मीडिया में इस खबर को प्रमुखता नहीं दी गई. नतीजतन, इस मुद्दे पर एक सप्ताह तक अफवाहों का बाजार गर्म रहा. इसके बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने एक ट्वीट कर इतना भर कहा कि यह खबर गलत है. ऐसी कोई भी मांग सरकार ने नहीं स्वीकार की है. लेकिन इन दौरान केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान (प्रेस रीलिज के तौर पर न कि ट्वीट के तौर पर) नहीं आया, जो इन अफवाहों पर विराम लगा सके. बहरहाल, हम यहां पूर्वोत्तर की मीडिया में छपी रिपोर्टों को देखकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल यह मामला है क्या और इसमें कितनी सच्चाई है?

पिछले 18 जून को पूर्वोत्तर के स्थानीय अखबारों में यह खबर छपी कि भारत सरकार ने नगाओं के लिए अलग पासपोर्ट और ध्वज की मंजूरी दे दी है. मणिपुर का एक स्थानीय अखबार द संगाई एक्सप्रेस ने यह छापा कि मणिपुर के फुंगरैतांग में एक सार्वजनिक बैठक में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड

(एनएससीएन-आईएम) के नेता आरएच राइजिंग ने घोषणा की कि नगाओं के लिए अलग पासपोर्ट और ध्वज की अनुमति अब केंद्र सरकार ने दे दी. दूसरी रिपोर्ट द नॉर्थ इस्ट ट्रूडे में लिखा गया है कि भारत सरकार ने नगाओं के लिए अलग पासपार्ट और ध्वज के लिए मंजूरी दे दी है. हालांकि नगालैंड के स्थानीय अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों ने इस घटना को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया. स्थानीय अंग्रेजी दैनिक नगालैंड पेज की संपादक टी मोनालिसा का मानना है कि विभिन्न गुटों के कई नेता इस तरह की घोषणाएं

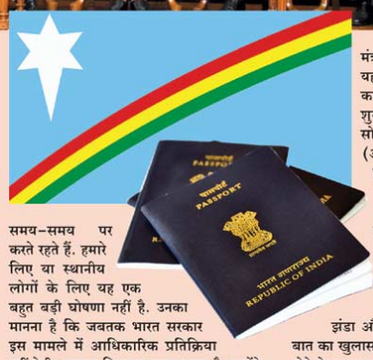

समय-समय पर करते रहते हैं. हमारे लिए या स्थानीय लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी घोषणा नहीं है. उनका मानना है कि जबतक भारत सरकार इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं देती, तबतक विश्वास करना गलत है. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों में आम राय है कि लोगों ने किसी भी गुट को आम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जनादेश नहीं दिया है.

अब यह खबर सही है या गलत, यह एक अलग विषय है. लेकिन इन खबरों ने कहीं न कहीं समाज में एक अंतर्विरोध तो पैदा किया ही है. एक तरफ मणिपुर में हुई उस सार्वजनिक बैठक में एनएससीएन-आईएम के स्वघोषित गृह मंत्री ने बेझिझक ऐलान किया कि नगाओं के लिए केंद्र सरकार ने अलग पासपोर्ट और ध्वज की मंजूरी दी, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री इस बात से इंकार कर रहे हैं. यह बात आम लोगों में शक पैदा कराता है. अगस्त 2015 की शुरुआत में केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) के बीच बातचीत शुरू हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया था. लेकिन अब पूर्वोत्तर के कुछ समाचार पत्रों ने इस समझौते पर सवाल खड़े कर दिए. यह तो तय है कि नगालैंड में शांति समझौते के अनुसार नगा अपना अलग झंडा और पासपोर्ट की मांग रखेंगे. इस बात का खुलासा आश्चर्यजनक रूप से समझौता होने के लगभग एक साल बाद हुआ है और केंद्र सरकार ने भी इस पर चुप्पी साध ली है. मुख्यधारा की मीडिया ने भी इस पर कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया, जबकि उत्तर पूर्व के स्थानीय समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है.

गौरतलब है कि एनएससीएन-आईएम नगा विद्रोहियों का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसका केंद्र सरकार के साथ संघर्ष विराम चल रहा है. इसी ग्रुप का दूसरा गुट एनएससीएन-के एसएस खपलांग के नेतृत्व में है, जो लगातार हिंसा का रास्ता अपनाए है. जून 2015 को मणिपुर में हुई मुठभेड़ में 18 जवान शहीद हुए थे. इसमें भी खपलांग का हाथ था. एनएससीएन-आईएम का मानना है कि नगाओं के लिए अलग ध्वज जरूर होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर का अलग ध्वज हो सकता है, तो नगाओं के लिए क्यों नहीं?

इस युद्ध विराम समझौते की नींव 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के कार्यकाल में पड़ी थी. केंद्र सरकार ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक क़दम बताया है और मुइवा भी इससे खुश नज़र आ रहे हैं. मुइवा की मांग एक वृहत नगालैंड की है, जिसमें पड़ोसी राज्य मणिपुर के चार ज़िले, अरुणाचल प्रदेश के दो ज़िले और असम के दो पहाड़ी ज़िले भी शामिल हैं. इस मामले को लेकर तीनों राज्यों में विरोध के स्वर शुरू से उठते रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ़ इतना बताया है कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में पड़ोसी राज्यों का पूरा ख्याल रखा गया है.

एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुइवा की ग्रेटर नगालैंड की मांग क्या पूरे नगा समुदाय की मांग है? क्या इससे सारे नगा खुश हैं? नगाओं में और भी कई सशस्त्र विद्रोही संगठन हैं. मुइवा का प्रमुख विरोधी गुट है, एनएससीएन (के), जिसकी कमान खपलांग के हाथ में है. इतना ही नहीं, एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट), जिसकी सशस्त्र शाखा एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) है, का मानना है कि इस समझौते के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य एनएस-सीएन (आईएम) के दोनों नेताओं ईसाक चिसी और टीएच मुइवा की ढलती उम्र का फ़ायदा उठाना भर है, यह जनता के हित में नहीं है और नगा जनता इन दोनों नेताओं से ऊपर है. एनएस-सीएन (आईएम) नगाओं का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है. इन संगठन का कहना है कि छह दशकों से चला आ रहा नगाओं का संघर्ष केवल आर्थिक पैकेज या ग्रेटर ऑटोनोमी के लिए नहीं है. इस दौरान नगाओं ने बड़ी संख्या में अपनी जान गंवाई. इस समझौते के अंतिम रूप लेने से पहले आईएम के नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए. बहरहाल, एनएससीएन (आईएम) और केंद्र सरकार के बीच जारी वार्ता तभी शांति वार्ता कहलाएगी, जब इसमें पड़ोसी राज्यों का समुचित ख्याल रखा जाएगा, अन्यथा आशंका है कि इस क्षेत्र में माहौल और बिगड़ सकता है. केंद्र सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. ■

sbijensngh@gmail.com

एनएससीएन-आईएम अध्यक्ष ईसाक चिसी सू का निधन

केंद्र सरकार से वार्ता कर रहे नगा विद्रोही गुट एनएससीएन-आईएम के अध्यक्ष ईसाक चिसी सू का निधन 28 जून को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में ऑर्गन फेल्योर की वजह से हो गया. 87 वर्षीय ईसाक का पिछले एक साल से दिल्ली में इलाज चल रहा था. नगालैंड के जूनहेबोटो जिले में जन्मे ईसाक सूमी (नगा) आदिवासी थे. नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) और केंद्र सरकार के बीच हुए शिलांग समझौते के विरोध में ईसाक और मुइवा के साथ मिलकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आईएम) 1980 में बना था. 1997 में एनएससीएन आईएम केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू हुआ था. इन 16 सालों में लगभग 80 बैठकें हो चुकी हैं. ईसाक 1950 में एनएनसी में शामिल हुए थे. 1980 में एनएनसी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य संभालते रहे. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ईसाक को नगा शांति वार्ता में उनके ऐतिहासिक भूमिका के लिए याद किया जाएगा. वे नगा समुदाय की शांति चाहते थे. उनके निधन का असर नगा शांति वार्ता पर पड़ना तय है. ■

पंजाब और गोवा चुनाव पर आम आदमी पार्टी का ध्यान

केजरीवाल के बूते बढ़ती आप

चंदन राय

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पार्टी में वे महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि पार्टी महत्वपूर्ण है. गोवा में चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जब यह कह रहे थे तो साथ ही यह भी दिख रहा था कि आप में उनके अलावा प्रस्तुति लायक कोई दूसरा बड़ा चेहरा पार्टी में नहीं है. केजरीवाल से यह पूछा गया था कि क्या उनकी छवि आम आदमी पार्टी से बड़ी बन रही है. अरविंद केजरीवाल इस बात से सहमत नहीं होने का उपक्रम करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और गोवा में सशक्त दावेदारी पेश करने के बाद भी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं, जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सके. आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष कहते हैं, यह रणनीति की बात है कि हम इन चुनावों में सीएम पद के उम्मीदवार के साथ आगे बढ़ें या नहीं. वे कहते हैं कि हमारे पास कई योग्य नेता हैं जो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं. आशुतोष की बातों के समानान्तर सच यही है कि अरविंद के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं जिसके बूते इन राज्यों में चुनावी वैतरणी पार करने का जोखिम उठाया जा सके. यही कारण है कि अरविंद बार-बार इन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. उन्हें लोगों से कहना पड़ रहा है कि सही वक्त पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता का चुनाव होगा.

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी की नजर अभी पंजाब और गोवा चुनाव पर टिकी है. पंजाब में ड्रग्स तस्करों और राजनीतिकों के नेक्सस को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है. चुनाव से पहले उड़ता पंजाब फिल्म ने चुनाव की पटकथा तैयार कर दी है, बस अब चुनावी बिगुल फूंके जाने का इंतजार है. वहीं, कांग्रेस पार्टी अभी पंजाब में चुनाव प्रभारी तय करने में ही उलझी हुई है. अन्य पार्टियां यह प्रचार करने में जुटी हैं कि जो पार्टी अपना चुनाव प्रभारी तक नहीं तय कर पा रही है, वह किस बूते चुनाव लड़ेगी. कांग्रेस के रणनीतिकारों को अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है. कांग्रेस इस राज्य में फिर वापसी करने के इंतजार में है. नशे का बढ़ता कारोबार और एंटी इनकमबेंसी फैक्टर सत्तारूढ़ अकाली दल-भाजपा की राह का रोड़ा बने हैं. आप का मानना है कि बादल सरकार

पर भ्रष्टाचार के आरोप और अकाली दल-भाजपा में अनबन की खबरों से उकताए लोग अब राज्य में बदलाव चाहते हैं. आप इन सभी मुद्दों को भुनाने की तैयारी में पहले से ही मैदान में है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव प्रभारी तय करने की विफलता से निराश हैं. आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए वीडियो जारी कर दिया गया है. वीडियो के अंत में पांच साल केजरीवाल गाना बजता है. अब ड्रग्स, भ्रष्टाचार छंटने वाला है, केजरीवाल आने वाला है के नारों से यह तय है कि यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना है. ये ऐसे चुनावी मुद्दे हैं, जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी बेबस नजर आती है.

राजनीतिक दल केजरीवाल को सियासी डगर पर सधे कदम से, बिना डिगे खामोशी से बढ़ता देखकर हतप्रभ भी हैं और चौकन्ने भी. तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणियों को धता बताते हुए अरविंद गोवा व पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान किसी हड़बड़ी में नहीं दिखते हैं. वे आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए अपने को उन लोगों के बीच का आम आदमी बताना भी नहीं भूलते. लच्छेदार भाषणों के बजाय आमफहम भाषा में संवाद अदायगी के अंदाज पर जनता भी खुश है. उनके विरोधियों को लगता है कि केजरीवाल सादगी का विज्ञापन करने में माहिर हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास से भरे केजरीवाल हार से सबक लेने के बाद अब राष्ट्रीय पटल पर एक मंजे राजनीतिक की तरह उभरे हैं.

यही कारण है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से सत्तारूढ़ भाजपा समेत अन्य पार्टियों में खलबली मची है. अरविंद गोवा में जनता से एक ही बात कहते हैं, हम 40 में से 35 सीट जीत रहे हैं. अब राष्ट्रीय पार्टियों को उनका यह आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता. एक समय गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि जिस तरह बाजार में नए और अनजान व्यापारी का चेक नहीं चलता, उसी तरह केजरीवाल राजनीति में नए हैं, जनता को पहले उन्हें दो-तीन साल तक परखना चाहिए. इस बयान के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है. अब उनके धुर राजनीतिक विरोधियों को भी पता है कि अरविंद चुनावी बिसात को पलटने का दम-खम रखते हैं. दिल्ली चुनाव का भयानक सच आज भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करता है. उन्हें डर है कि कहीं गोवा और पंजाब में भी उनकी हालत दिल्ली जैसी न हो जाए.

पंजाब में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी दबे मन से यह स्वीकार करते हैं कि यहां के चुनाव में फिलहाल आप को बढ़त हासिल है. आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष कहते हैं, हमें पता है कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अपील है. लेकिन चुनावी समर में उतरने से पहले हम अपना संगठन मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र और सभी दक्षिणी राज्यों में सांगठनिक स्तर पर प्रमुखता से काम हो रहा है. पंजाब में चार लोकसभा सीट जीतने के बाद से ही पार्टी विस्तार के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी थी. पंजाब, गोवा के बाद गुजरात में भी आम आदमी पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है. नरेंद्र मोदी को घर में ही घेरने की तैयारी में आप के रणनीतिकार जुटे हैं. गुजरात के कथित विकास मॉडल को चुनौती देने के लिए दिल्ली का विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है. राष्ट्रीय पटल पर मोदी विरोधी की पहचान बनाकर केजरीवाल समाज के एक धड़े को पार्टी के साथ जोड़ने में सफल रहे हैं. गोवा और पंजाब के चुनाव में केजरीवाल अगर अपनी यह पहचान बनाए रखने में सफल रहे, तो राष्ट्रीय फलक पर वे एक मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सांसद ने गोद लिया और फिर अनाथ छोड़ दिया

अच्छे दिनों पर भारी आदर्श ग्राम पठारी

महोबा के इस गांव में आजादी के बाद से अब तक पानी, बिजली, सड़क नदारद

इसरार पठान

मोदी का नाम आते ही अच्छे दिनों का ख्वाब ताजा हो जाता है. अच्छे दिन आने के दावे और वादे की उम्र दो साल हो चुकी है. लेकिन इंतजार जारी है. यह इंतजार 67 वर्षों से जारी है. प्रधानमंत्री की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं का यूपी के बुंदेलखंड में बुरा हाल है. यहां के अधिकांश आदर्श गांव बदहाली का शिकार हैं, इस क्षेत्र में शामिल एक गांव तो ऐसा भी है जहां न सड़क है न पानी. एक हजार आबादी वाले इस गांव में आजादी से आज तक बिजली के दर्शन नहीं हुए. हमीरपुर-तिन्दवारी लोकसभा से भाजपा सांसद के इस दत्तक गांव का कोई पुरसाहाल नहीं है.

महोबा जनपद का ग्राम पठारी पिपरा माफ प्रधानमंत्री के अच्छे दिनों के वादे पर जोरदार तमाचा है. सड़क, बिजली और पानीविहीन इस गांव का दुर्भाग्य है कि यहां की एक हजार आबादी इक्कीसवीं सदी में चौदवीं सदी का जीवन गुजार रही है. कहने को तो इसे हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी से भाजपा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने गोद ले रखा है, पर इन दो वर्षों में वह इस गांव में फकत एक बार पहुंच सके. ऐसा नहीं कि इस गांव की हालत से शासन प्रशासन अनभिज्ञ हो, ग्रामीण अपनी व्यथा डीएम से लेकर पीएम तक, सभी को सुना चुके हैं, पर हर बार परिणाम सिफर ही रहा. ग्रामीण कहते हैं कि आज तक उनकी किसी ने नहीं सुनी. गामीणों की मानें तो जब से यह गांव आदर्श ग्राम घोषित हुआ तब से इसकी दशा और भी बदतर हो गई. आदर्श ग्राम होने के चलते जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा और सांसद को यहां आने की फुर्सत नहीं है. डिजिटल इंडिया जैसे शब्द से अंजान इस गांव के लोग आधुनिकता की दौड़ में कितने पीछे हैं इसका अनुमान लोगों के घरों में जलने वाली लालटेनों से लगा सकते हैं. देश का यह पठारी पिपरा माफ गांव उन दुर्भाग्यशाली गांवों में शुमार है, जहां आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची. यूपी सीमा के अंतिम छोर पर बसे इस गांव में केवल विद्युत अनुपलब्धता ही बड़ी समस्या नहीं, गांव की कच्ची सड़क, जस संसाधन का अभाव और पगडंडियों में व्याप्त गंदगी ने भी ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर रखा है. आज भी यहां के लोग मुख्य सड़क से तीन किलोमीटर कच्चा रास्ता तय कर गांव पहुंचते हैं. आम दिनों में तो जैसे-तैसे काम चल जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में ग्रामीणों की दुश्वारियां बहुत बढ़ जाती हैं. अस्पताल और स्कूल के नाम पर भी यहां कुछ नहीं है. रही बात पानी की तो गांव के बाहर लगे एक मात्र हैंडपम्प से 250 परिवार काम चला रहे हैं. बुंदेलखंड के महोबा में पानी को लेकर जो हालात हैं वह सभी जानते हैं ऐसे में गांव के लिए यह हैंडपम्प किसी वरदान से कम नहीं. तड़के चार बजे से इस हैंडपम्प पर लगा साइकिलों और बैलगाड़ियों का जमावड़ा गांव में गहराते पानी संकट की कहानी बयान करता है.

सफाई के मामले में भी इस मजरे की दशा बेहद खराब है. यह गांव जिस पिपरा माफ ग्राम पंचायत में शामिल है, उसकी कुल आबादी दस हजार है और इस बड़ी आबादी के लिए मात्र एक सफाईकर्मी तैनात है. यह तथ्य बताता है कि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान और मुख्यमंत्री का क्लीन यूपी ग्रीन यूपी अभियान इस ग्राम पंचायत में कितना कारगर हो रहा होगा. इस ग्राम पंचायत को मिले शौचालयों का धन पहले ही गांव के पूर्व प्रधान और सचिव ने मिलकर डकार लिए. नतीजे के तौर पर ग्रामीण आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं. अधिकांश ग्रामवासियों के पास मोबाइल नहीं है, और जिनके पास है वह पड़ोस के गांव से चार्ज कर काम चलाते हैं. फ्रिज टीवी, स्टीरियो और डीवीडी किस बला का नाम है, पठारी के ग्रामीण जानते तक नहीं. इस गांव की हालत देखकर आप प्रधानमंत्री के अच्छे दिनों की असलियत समझ और परख सकते हैं. असल में पठारी गांव मोदी के कथित विकास को मापने का वह थरमामीटर जो उनके सभी दावों को झूठा साबित कर रहा है. गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी नवाब सिंह परिहार कहते हैं कि सांसद ने ग्रामीणों के साथ छलावा किया है. बकौल नवाब सिंह, वह खुद कई बार सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से मिल चुके हैं, पर वह कोई ध्यान नहीं दे रहे. ग्राम प्रधान घसीटा अनुरागी को भी इस बात का खासा मलाल है कि उनकी ग्राम पंचायत के साथ प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है. प्रधान के मुताबिक उनकी ग्राम पंचायत में पिपरा माफ के साथ कंचनपुरा, उदयपुरा और पठारी जुड़े हुए हैं, इन सब की कुल आबादी दस हजार है और इस आबादी के लिए मात्र एक टैंकर दिया गया है, जिससे जलापूर्ती करने में बहुत दिक्कत हो रही है. सफाईकर्मियों की भी कमी है जिसके चलते सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही. घसीटा अनुरागी का क्हना है कि आदर्श गांव होने के बाद भी पठारी प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है.■

feedback@chauthiduniya.com

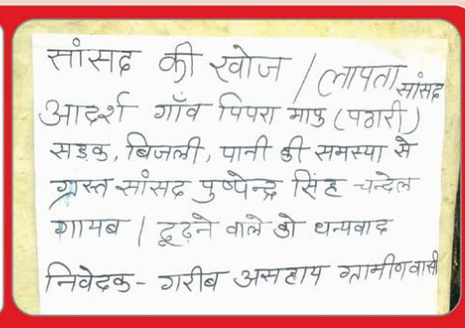

हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की उदासीनता को लेकर पठारी ग्रामवासी ही नाराज नहीं हैं, इनके लोकसभा क्षेत्र में शामिल अधिकांश गांवों के लोगों को सांसद की लापरवाह कार्यशैली खल रही है. सभी की यह शिकायत आम है कि पुष्पेंद्र सिंह चंदेल माननीय बनते ही गायब हो गए हैं. गांवों में चस्पा सांसद के लापता होने के पोस्टर ग्रामीणों के इस बयान की तस्दीक कर रहे हैं. लोगों का आरोप है कि जरूरत पड़ने पर माननीय का फोन भी नहीं लगता. ग्रामीणों के इस आरोप को जांचने के लिये चौथी दुनिया संवाददाता ने भी सांसद को फोन लगाया. कई बार घंटी जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई. लोकसभा क्षेत्र के अन्य गांवों की तरह पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के अपने ग्रामवासी भी उपेक्षा के शिकार हैं. कैमाहा गांव के लोगों का कहना है कि सांसद की इसी उपेक्षापूर्ण नीति का खामियाजा उनके पिता ग्राम प्रधान चुनाव को हार कर भुगत चुके हैं, लेकिन सांसद इससे कोई सीख नहीं लेते.■

सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल अपनी कार्यशिथिलता के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि वह गरीबों की जमीन हथियाने के मामलों में कुख्यात हैं. ग्राम समाज और नजूल से लेकर लोगों की निजी जमीनों तक पर इनका कब्जा है. अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐसे ही अंधे गरीब टिर्रा प्रजापति की जमीन धोखे से हथिया लिए जाने के मामले को लेकर सांसद किरकिरी झेल चुके हैं. फिलहाल यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. विकलांग टिर्रा के पुत्रों लक्ष्मी एवं सुन्दरलाल का आरोप है कि सांसद ने अपने एक गुर्गे गोविन्द यादव के माध्यम से पिता को बुलवाया और पेंशन फॉर्म बताकर उसपर हस्ताक्षर ले लिए. भटीपुरा के रहने वाले इस गरीब की भूमि बेशकीमती है, जिस वजह से सांसद की लोलुप निगाह पड़ गई. पीड़ित परिवार ने अपने साथ हुए अन्याय को लेकर खूब शिकायतें कीं और धरना-प्रदर्शन किये पर सांसद की हैसियत के आगे उनकी एक नहीं सुनी गई. कभी भाजपा का कट्टर समर्थक रहा यह परिवार अब सांसद की करतूतों के कारण पार्टी की आलोचना करता घूम रहा है.■

अपना पेट हाऊ न देहो काऊ

बुंदेलखंड की एक मशहूर कहावत है, अपना पेट हाऊ - न देहो काऊ. हमीरपुर-महोबा-तिंदवारी सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की कार्यशैली पर यह कहावत सटीक बैठती है. सांसद द्वारा गोद लिए गांव पठारी के विकास की फिक्र भले न हो पर वह खुद की तरक्की को लेकर बड़े गंभीर रहते हैं. सांसद के नाम पर चल रहे पेट्रोल पम्प, क्रशर, पहाड़, काऐलेज और कामधेनु योजना के नाम पर स्थापित एक करोड़ लागत की डेयरी उनके विकास-पसंद होने का पुख्ता प्रमाण है, पर यह विकास उनका निजी है. पुष्पेंद्र देश के उस सदन के सदस्य हैं, जहां कानून बनाए और लागू किए जाते हैं, ऐसे में इनपर कानून का पालन करना बेहद लाजमी हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं. यही वजह है कि इनके क्रशर प्लान्टों पर नियम-कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं. कबरई के डहर्रा में इनके नाम पर हो रहा पत्थरों का अवैध खनन भी कानून के प्रति इनके गैरजिम्मेवारी को ही दर्शाता है. सांसद के पेट्रोल पम्पों में भी नियमों की खूब खिल्ली उड़ाई जाती है. सांसद अपने निज-विकास को लेकर कितने संजीदा हैं, इसका उदाहरण है उस योजना को हथियाया जाना, जिसे बुंदेलखंड की दशा सुधारने के लिए लागू किया गया था. कामधेनु योजना पर सांसद की नजर गड़ गई और उन्होंने इस योजना को ही अपने कब्जे में ले लिया. एक करोड़ 20 लाख की इस योजना के लिए दो आवेदन मांगे गए थे जिसमें एक सांसद के पिता हरपाल सिंह का स्वीकृत किया गया जबकि दूसरा आवेदन भी सांसद के ही एक करीबी का स्वीकृत हुआ. हालांकि लायक सिंह ने बाद में अपना आवेदन वापस ले लिया.

सांसद के पिता हरपाल सिंह के आवेदन को स्वीकृत हुए भी दो साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कामधेनु योजना चालू नहीं हो सकी. बताते हैं कि निर्माण कार्य के लिए बैंक की तरफ से फंड रिलीज हो चुका है पर भवन अभी भी आधा-अधूरा ही पड़ा है. पठारी गांव से चंद किलोमीटर की दूरी पर माननीय के गांव में बन रहा यह भवन भले अभी निर्माणाधीन अवस्था में हो, पर इस भवन की आड़ में नाले पर कब्जा पूरा हो चुका है. भवन को बनाने के लिए सांसद ने न केवल नाला पाट दिया, बल्कि उस पर बने चेकडैम को ही उखाड़ फेंका. बुंदेलखंड में भीषण जल-संकट है और मवेशियों सहित आम जनता बूंद-बूंद पानी के लिये संघर्ष कर रही है, ऐसे में सांसद का यह कदम कितना जनहित और लोकतांत्रिक है, इसे समझा जा सकता है.■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

प्राचार्य नियुक्ति घोटाला

एमयू पर निगरानी की नज़र

निगरानी विभाग ने विभिन्न दस्तावेजों की मांग करते हुए मगध विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 17 जून 2016 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी अरुण शुक्ल के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम ने मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित कुलसचिव के कार्यालय में पहुंचकर प्राचार्य घोटाले से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की मांग की. टीम ने मगध विश्वविद्यालय से इस बहाली से संबंधित नोटिफिकेशन, 16 जनवरी 2013 से नियुक्त 12 व तीन अन्य प्राचार्यों का वर्तमान पदस्थापना, पद सहित प्रत्येक का विवरण, नियुक्त प्राचार्य पद और वेतन का लाभ ले रहे हैं के संबंध में जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बिहार का सबसे बड़ा मगध विश्वविद्यालय दो वर्षों से वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ी के कारण चर्चा में है. वर्तमान कुलपति समेत कई पूर्व कुलपतियों पर पुलिस व निगरानी विभाग में कई मामले दर्ज हैं. फिलहाल निगरानी विभाग जनवरी 2012 में मगध विश्वविद्यालय में बहाल किए गए 12 प्राचार्यों के मामले की जांच में जुटा है. 17 जून 2016 को निगरानी विभाग की टीम ने मगध विश्वविद्यालय जाकर इस मामले से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को जब्त किया. इस मामले में पूर्व कुलपति अरुण कुमार आरोपी हैं. वे बिहार टॉपर घोटाले के आरोपी लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी प्रो. उषा सिंह के संबंधी हैं. प्राचार्य नियुक्ति घोटाले में प्रो. उषा सिंह को भी गलत तरीके से प्राचार्य के पद पर नियुक्त करने का आरोप अरुण कुमार पर है. पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो वित्तीय वर्ष 2012-13 में मगध विश्वविद्यालय में 15 प्राचार्यों की नियुक्ति की जांच कर रही है.

निगरानी विभाग ने विभिन्न दस्तावेजों की मांग करते हुए मगध विश्वविद्यालय पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 17 जून 2016 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी अरुण शुक्ल के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम ने मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित कुलसचिव के कार्यालय में पहुंचकर प्राचार्य घोटाले से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की मांग की. टीम ने मगध विश्वविद्यालय से इस बहाली से संबंधित नोटिफिकेशन, 16 जनवरी 2013 से नियुक्त 12 व तीन अन्य प्राचार्यों का वर्तमान पदस्थापना, पद सहित प्रत्येक का विवरण, नियुक्त प्राचार्य पद और वेतन का लाभ ले रहे हैं के संबंध में जानकारी व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे हैं. इसके अलावा उनके पदस्थापन के संबंध में जानकारी, 12 अप्रैल 2012 को संपन्न मगध विश्वविद्यालय सिंडिकेट व एकेडमिक काउंसिल की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका, वर्ष 2009 में हाईकोर्ट द्वारा तत्कालीन प्राचार्य बहाली के रद्द किए जाने के संबंध में दिए गए न्यायादेश की कॉपी, 12 व तीन प्राचार्य बहाली के संबंध में प्रिंट मीडिया व विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नोटिफिकेशन के प्रमाण मांगे हैं. निगरानी की टीम ने मगध विश्वविद्यालय से जनवरी 2013 से मई 2013 तक का विश्वविद्यालय का लेटर डिस्पैच रजिस्टर, 18 फरवरी 2013 को हुई बैठक की एजेंडा की कॉपी और प्रोसीडिंग्स की अभिप्रमाणित कॉपी ली. टीम ने 2012-13 के पहले मगध विश्वविद्यालय में प्राचार्य की बहाली से संबंधित कागजात भी लिए. निगरानी की टीम ने 8 अप्रैल 1988, 21 अप्रैल 1994 तथा 2 मार्च 2012 में हुई प्राचार्य बहाली की जानकारी ली.

2012-13 में मगध विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार ने 15 प्राचार्यों की बहाली की थी. इस बहाली के दौरान मगध विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन किया गया था. इस नियुक्ति में तीन अतिरिक्त का चयन किया गया था. इस बहाली में गड़बड़ी और गलत तरीके से प्राचार्यों की नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद राजभवन ने बीबी लाल के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि की थी. इसके बाद अप्रैल 2015 में पटना हाईकोर्ट ने प्राचार्यों की नियुक्ति की जांच का आदेश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दिया था. बीबी लाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्राचार्य बहाली के लिए गलत तरीके से चयन समिति का गठन किया गया. इसके अलावा आवेदन के लिए नियमानुसार 45 दिनों का समय नहीं दिया गया, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया, साक्षात्कार में मनमाने तरीके से अंक दिए गए, मेघा सूची में गड़बड़ी की गई, मेघा में शून्य अंक दिये गए समेत कई अनियमितताओं का जिक्र जांच कमेटी ने किया.

निगरानी के इस मामले में मगध विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति अरुण कुमार, तत्कालीन कुलसचिव डीके यादव, डिप्टी रजिस्ट्रार फैहीमुद्दीन, चयन समिति के सदस्य और गया कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य श्रीकांत शर्मा, राजभवन के प्रतिनिधि बालेश्वर पासवान, कुमारेश प्रसाद सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शशि प्रताप शाही, प्रवीन कुमार, उपेन्द्र प्रसाद, दिनेश प्रसाद सिंह, ब्रजेश कुमार रॉय, उषा सिन्हा, पूनम, रेखा कुमारी, शिला सिंह, इन्द्रजीत रॉय, कृष्णनन्दन यादव, अरुण रजक, वेदप्रकाश चतुर्वेदी, दलवीर सिंह तथा सुधीर कुमार मिश्रा आरोपी हैं. इसके अलावा मगध विश्वविद्यालय के मुख्यालय में मीटिंग सेक्शन के इंचार्ज व वर्तमान में गया कॉलेज के प्राचार्य शमशुल इस्लाम और मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय में सहायक यूएन सहाय को भी अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति रद्द करते हुए अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है. इसके साथ ही निगरानी को जांच का आदेश दिया गया था. इस बहाली में 12 प्राचार्यों के अलावा तीन अतिरिक्त प्राचार्यों में ब्रजेश रॉय, कृष्णनन्दन यादव तथा उषा सिन्हा का नाम शामिल है. बाद में उषा सिन्हा को पटना स्थित गंगादेवी महिला कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया था. उषा सिन्हा बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहे लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी हैं. फिलहाल दोनों पति-पत्नी बिहार टॉपर घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं. उषा सिन्हा को तमाम नियमों को ताख पर रख प्रमोशन देते हुए प्राचार्य बनाया गया था. वे जदयू की विधायक भी रह चुकी हैं और सत्ताधारी दल में दोनों पति-पत्नी की मजबूत पकड़ थी. निगरानी विभाग की जांच से मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं जांच के दायरे में उनका नाम भी न आ जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

दांतों के साथ मसूढ़ों का भी रखें ख्याल

ariskon Pharma Pvt.Ltd
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. रंजन कुमार (BDS)
MANSI DENTAL, M.G.M, KHAGARIA.

मानसी डेन्टल क्लिनीक, महात्मा गांधी मार्ग खगड़िया से डॉक्टर रंजन कुमार जो कि दांतों के अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं ने दांतों के साथ - साथ मसूढ़ों के प्रति भी सजग रहने को कहा।

उनके शब्दों में सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है स्वस्थ्य दांत, और दांत न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं,बल्कि हमारे लूक को अच्छा बनाते हैं जिससे व्यक्तित्व में निखार आता है। उन्होंने बताया कि दांतों की चमक तो बरकरार रखनी जरूरी है ही साथ ही मसूढ़ों की हिफाजत करनी चाहिए इसके लिए जरूरी है कि आप रात में सोने से पहले ब्रशींग के साथ मुंह में अपनी साफ अंगुली डालकर चारो ओर घुमायें साथ ही सुबह भी या जब भी आप खाना या नाश्ता करते हैं तो हाथ धोने के वक्त यह भी जरूरी हो जाता है कि आप मसूढ़ों पर अपनी अंगुलियों से मलिश करें या सफाई करें। डॉ. रंजन ने बताया कि हर छः महिने में आपको चाहिए कि आप दांतों के कुशल चिकित्सक से मिलकर चेकअप करवाते रहें। दांतों के सड़ने की वजह यह मानी जाती है कि आपके दांतों और मसूढ़ों के बीच कुछ फंसा हुआ न रहे। उन्होंने बताया कि फाइबर फुड के साथ रसेदार शब्जी भी प्रयोग करें फलों का खाने में प्रयोग करें जिससे दांत स्वस्थ्य रह सके। डॉ.रंजन कुमार ने बताया कि दांतों की सुरक्षा में कोताही न करें, दो बार ब्रशिंग तो जरूरी है ही साथ ही समय देकर अच्छे से ब्रश करें जिससे मसूढ़े स्वस्थ्य होंगे। यदि आपके दाँत टूट रहे हैं तो उसे निकालने के बजाय उसे बचाने का प्रयास करें और यदि टूट जाता है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर प्रत्यारोपण करा लें या फिर नया लगा लें और हर छहः महीने पर इसका चेकअप कराते रहें। दूध पिलाने के बाद कुल्ला, कराना, आवश्यक है, दांतों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है चिपचिपा फूड, चॉकलेट, बिस्कूट खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें जिससे पायरिया से भी बच सकते हैं। ▌-भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg

Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.

Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org, Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

Name of Courses		Eligibility	Duration
POST GRADUATE COURSES :			
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

उत्तराखंड में तेज हो रही सियासी जोर आजमाइश

सपा भी बांध रही मंसूबे

फोटो-प्रभात पाण्डेय

धर्मेंद्र कुमार सिंह

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जोर-आजमाइश करनी शुरू कर दी है. समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी हैं. सपा की रणनीति पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह है. माना जा रहा है कि उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कन्नौज से सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है. डिंपल यादव उत्तराखंड की हैं और सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहती है. समाजवादी पार्टी की तैयारियों की उत्तराखंड की दो बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समीक्षा कर रही हैं. भाजपा ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है. हाल ही में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया और उन्होंने शंखनाद महारैली के साथ 2017 विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की. उससे पहले अमित शाह ने भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए. उत्तराखंड को लेकर अमित शाह की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले वह दर्शन के लिए हेलिकॉप्टर से जाने वाले थे, पर बाद में उन्होंने यह प्लान बदल दिया और सड़क के रास्ते से गए. ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जो भी हेलिकॉप्टर से गया उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी. बद्रीनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूर्व सीएम एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह, डॉ रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी.

पर्वत प्रदेश की राजनीति का समीकरण कांग्रेस के कद्दावर नेता विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, अमृता रावत समेत नौ बागी नेताओं के भाजपा में शामिल होने से गड़ड-मड़ड हो गया. लेकिन जद्दोजहद कर अपनी सत्ता बचा पाए मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं. हालांकि अभी उत्तराखंड की सत्ता पर बरकरार कांग्रेस सरकार बसपा और निर्दलीय विधायकों के सहारे चल रही है, लेकिन धीरे-धीरे रावत अपनी जमीन पुख्ता करने में लगे हैं.

उधर, समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में डिंपल यादव को चेहरा बनाकर सत्ता पर काबिज होना चाहती है. डिंपल उत्तराखंड में पौड़ी जिले के कोटद्वार में जन्मीं और पली-बढ़ी हैं. सपा को लगता है कि वह राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करा सकती है. वर्ष 2000 से पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का खासा प्रभाव था. अलग राज्य के लिए उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हुए और इस आंदोलन में कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ीं. सपा उत्तराखंड के विभाजन के खिलाफ थी और वह नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो. इसके बाद से सपा को उत्तराखंड के लोग पृथक राज्य आंदोलन के विरोधी के तौर पर देखने लगे. उत्तराखंड की 23 सदस्यी अंतरिम विधानसभा में सपा के तीन विधायक थे उसके बाद सपा तमाम कोशिशों के बावजूद उत्तराखंड में हुए तीनों विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल सकी. सपा का कहना है कि राज्य में उनकी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी है और कांग्रेस एवं भाजपा दोनों के कुशासन से त्रस्त जनता विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को दोबारा अपनाना चाहती है. सपा का कहना है कि हम लोग यहां के लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी सपा की सरकार होने से हमें परिसंपत्तियों के बंटवारे सहित सभी मोर्चों पर लाभ होगा और इसका फायदा जनता को ही मिलेगा. अब बदलते परिदृश्य को देखते हुए सपा भी डिंपल यादव के जरिए उत्तराखंड के लोगों को अपने पाले में लाना चाहती है.

सपा ने उत्तराखंड की सत्ता के लिए पूरा जोर लगा दिया है. शिवपाल यादव कई बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं. सपा ने कैराना की घटना की जांच के लिए पांच संतों की टीम बनाई. टीम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी. टीम में भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कृष्णन, हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी देवेन्द्रानंद गिरि, स्वामी कल्याण देव व स्वामी चिन्मयानंद शामिल थे. इनमें कांग्रेस और भाजपा से लगाव रखने वाले संत शामिल थे. सपा की रणनीति है कि उत्तराखंड में साधु-संतों को सपा के पाले में लाया जाए. इसके मद्देनजर ही सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं. साथ ही राजेन्द्र यादव मठों में जाकर संतों से मुलाकात भी कर रहे हैं. राज्य में सपा सबको साधने में लगी है और संतों के जरिए भी भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देना चाहती है.■

feedback@chauthiduniya.com

सुगबुगा रहा अलग सिख-प्रदेश बनाने का आंदोलन

सरदार अमीर सिंह विर्क

उत्तराखंड के निर्माण में सबसे अधिक अन्याय सिखों के साथ हुआ है. तराई इलाके में छाए सिख नागरिक नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड का बंटवारा हो. सपा से भी सिखों को भरोसा था कि तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ ही रह जाएगा. हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने हरिद्वार समेत तराई क्षेत्र के यूपी में बने रहने की आखिरी दम तक कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. तराई इलाके में सिखों की संख्या अधिक है और सिख समुदाय समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, अगर सपा सिखों के पक्ष में कोई घोषणा कर दे. सिखों को यह भी खलता है कि उत्तराखंड के लोगों ने सिखों को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्हें अब भी बाहरी समझते हैं. गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि 1984 के सिख दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे के रूप में किसी को पांच हजार, किसी को एक हजार और शर्म की बात तो यह है किसी को 70 रुपये के चेक मुआवजे के बतौर दिए गए. जबकि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. सिखों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी वजह से सिखों में राजनीतिक दलों को लेकर नाराजगी है. तराई के सिख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच अपना अलग राज्य चाहते हैं. तराई क्षेत्र के जुझारू सिख नेता अमीर सिंह विर्क कहते हैं कि लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ऊधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों को मिला कर सिखों के लिए अलग राज्य बनाने की मुहिम अंदर ही अंदर परवान चढ़ रही है. विर्क का दावा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य सिखों का प्रदेश स्थापित होगा और इसके लिए जल्द मद्धेशियों की तरह का आंदोलन तराई क्षेत्र में शुरू किया जाएगा.■

अमेठी तहसील परिसर में दिनदहाड़े किया गया हमला, पुलिस चुपचाप देखती रही

सपा नेता ने अमीन को पीट-पीट कर मार डाला

डॉ. पंकज सिंह

जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे-वैसे ही सपा के अपने ही नेताओं द्वारा सपा के लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं. कभी प्रदेश के खनन मंत्री भ्रष्ट-धन्य गायत्री प्रसाद प्रजापति के तांडव का दंश जनता को झेलना पड़ता है, तो कभी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन को नंगा करके दबंगई दिखाने का. बीते 21 जून को अमेठी विधानसभा क्षेत्र के सपा अध्यक्ष राकेश यादव ने संग्रह अमीन दान बहादुर यादव को तहसील परिसर में सीओ और उप जिलाधिकारी के सामने जमकर पीटा. जख्मी अमीन को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. पूरा तहसील प्रशासन इस हत्याकांड का मूकदर्शक बना रहा और सपा नेता का तांडव देखता रहा. किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि उस दबंग सपाई के कहर से राजस्व कर्मी को बचा सके.

आरोपी सपा नेता राकेश यादव अन्य अभियुक्तों के साथ पुलिस हिरासत में

मृतक अमीन दान बहादुर

बताते चलें कि सपा नेता राकेश यादव का दान बहादुर यादव (निवासी पूरे चैतराम पांडे थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी) से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. जिसके चलते राकेश आए दिन दान बहादुर को धमकियां देता रहता था. बीते 21 जून को राकेश अपने साथियों को लेकर लाठी डंडों के साथ तहसील परिसर पहुंचा. हथियारबंद लोगों ने राकेश यादव के नेतृत्व में संग्रह अमीन दान बहादुर पर हमला बोल दिया. राकेश यादव ने असलहे के बट से दान बहादुर के सिर पर वार किया जिससे दान बहादुर का सिर फट गया. मरणासन्न हालत होने के बाद ही राकेश यादव और उसके गुर्गों ने दान बहादुर को छोड़ा. पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा रहा और अमीन जान बचाने की गुहार करता रहा. जख्मी अमीन के परिवार वालों ने उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया. जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया. आठ दिनों तक दान बहादुर जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ते रहे, लेकिन 28 जून को उनकी मौत हो गई.

दुखद तथ्य यह है कि अमीन की दिनदहाड़े सब लोगों के सामने हत्या करने वाले सपा नेता राकेश यादव के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया. सरेआम हुई हत्या के बावजूद पुलिस द्वारा मौके पर कोई कार्रवाई नहीं करने के बारे में पूछने पर अमेठी जिले के पुलिस कप्तान हीरा लाल ने कहा कि बाद में दो मुख्य आरोपियों राकेश यादव और जगदीश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है.■

feedback@chauthiduniya.com

नेता-राग

अमेठी की पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस की नेता अमिता सिंह ने कहा कि सपा सरकार की लाचारी और प्रशासन की मक्कारी से आज अमेठी रो रहा है. अमेठी में चाहे अशोक सरोज की हत्या हो या फिर डॉ. पीके सिंह, जेपी मिश्रा, हरिद्वार सिंह, रणधीर सिंह वगैरह के मारे जाने का मामला, सबमें पुलिस पंगु बनी रही. मैं लगातार अमेठी के पुलिस-प्रशासन से लड़ती रही हूं. दानबहादुर की हत्या के बाद तो जैसे लगा कि पुलिस प्रशासन का कोई अस्तित्व ही अमेठी में नहीं बचा है. मैंने मुख्यमंत्री से मृतक के परिवार के लिए 25 लाख रुपये व उनके बेटे को त्वरित रूप से सरकारी नौकरी देने की मांग की है, साथ ही दबंगों के असलहों के लाइसेंस निरस्त करने की अपील भी की है. अभी तक अमेठी में इस तरह सार्वजनिक हत्या की घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन जब से सपा सत्ता में आई है, सपा के गुर्गे हत्या, लूट, वसूली, भूमि पर कब्जा और लड़कियों के अपहरण की वारदातें अंधाधुंध कर रहे हैं. मैंने अखिलेश को चुनौती दी है कि यदि स्थितियों पर तुरंत नियंत्रण नहीं हुआ तो व्यवस्था के ख़िलाफ मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगी.

अमिता सिंह

आशीष शुक्ला

उमा शंकर पांडेय

दूसरी तरफ बसपा नेता आशीष शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की बेजा कानून व्यवस्था का मैं लगातार विरोध कर रहा हूं. दान बहादुर की हत्या के बाद भी मैंने ही हस्तक्षेप करके एफआईआर दर्ज कराया और उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा था. भाजपा के जिलाध्यक्ष उमाशंकर पांडेय ने कहा कि अमेठी का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के दबाव में काम कर रहा है. जिसका परिणाम रहा कि दानबहादुर की हत्या के 24 घंटे के बाद भी पुलिस पीड़ित के पास नहीं पहुंची और न ही दोषियों के ख़िलाफ कोई कार्रवाई की. भारतीय जनता पार्टी ऐसे घृणित काम की निंदा करती है. उन्होंने कहा कि गायत्री प्रसाद की दबंगई और सपाइयों की गुंडई के विरोध में भाजपा आंदोलन करेगी. सपा के जिलाध्यक्ष छोटे लाल से दूरभाष पर सम्पर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

नेहरू नहीं होते तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता

सच्चाई यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के वैचारिक विकल्प के रूप में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी. दरअसल यह लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे पब्लिक सेक्टर के खिलाफ थे. जहां तक कश्मीर का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में जाने के लिए नेहरू को दोष देना चाहिए. एक सज्जन पुरुष होने के नाते उन्होंने ऐसा किया. भारत के इस फैसले का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करता रहा है. लेकिन जो बिंदु हमसे छूट रहा है वह यह है कि कश्मीर आसानी से पाकिस्तान में चला गया होता, अगर शेख अब्दुल्लाह (जो नेहरू और महात्मा गांधी के प्रशंसक थे) ने भारत के साथ रहने का फैसला नहीं किया होता. ये शेख अब्दुल्लाह थे जिन्होंने फैसला किया कि कश्मीर सेक्युलर भारत के साथ रहेगा न कि मुस्लिम पाकिस्तान के साथ. महाराजा हरि सिंह जो अलग-थलग पड़ गए थे और यह सोचते हुए कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है पाकिस्तान चले गए होते.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में एक समारोह का आयोजन हुआ. विषय की गंभीरता को देखते हुए अच्छा होता कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपना व्याख्यान देते. यदि उनके पास समय की कमी थी और यदि पार्टी को इसके लिए किसी को चुनना था तो वह व्यक्ति आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी के क़द का होना चाहिए था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से सीनियर नहीं तो बराबर क़द वाले ज़रूर हैं. अमित शाह को मुख्य वक्ता बनाना दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क़द को कम करने जैसा है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट के एक काबिल सदस्य थे. उनके पास उद्योग मंत्रालय था. पब्लिक सेक्टर के पक्ष में लिए जाने वाले शुरुआती फैसले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही थे. लोग इतिहास और घटनाएं भूल जाते हैं, इसलिए आज यह आसान हो जाता है कि सारा दोष नेहरू के सिर मढ़ दिया जाए और श्यामा प्रसाद मुख़र्जी की खूब तारीफ की जाए. ऐसी बातें बेतुकी हैं.

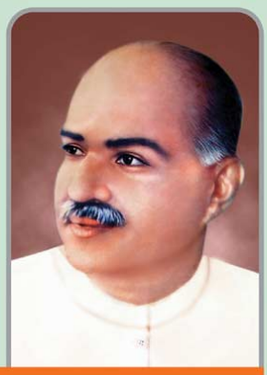

भाजपा के नीति निर्माताओं के बीच बड़ी भ्रान्ति फैली हुई है. मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस उनका मार्गदर्शन कर रहा है या नहीं. लेकिन अरुणाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में उनकी चालों से एक बात साफ़ हो रही है कि वे कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य जितना हो सके राज्य सरकारों को अपने हिस्से में कर लिया जाए, सिद्धांत और नीति से कोई मतलब नहीं है.

सच्चाई यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस के वैचारिक विकल्प के रूप में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी. दरअसल यह लोकतंत्र का हिस्सा है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे पब्लिक सेक्टर के खिलाफ थे. जहां तक कश्मीर का सवाल है तो संयुक्त राष्ट्रसंघ में जाने के लिए नेहरू को दोष देना चाहिए. एक सज्जन पुरुष होने के नाते उन्होंने ऐसा किया. भारत के इस फैसले का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करता रहा है. लेकिन जो बिंदु हमसे छूट रहा है वह यह है कि कश्मीर आसानी से पाकिस्तान में चला गया होता, अगर शेख अब्दुल्लाह (जो नेहरू और महात्मा गांधी के प्रशंसक थे) ने भारत के साथ रहने का फैसला नहीं किया होता. ये शेख अब्दुल्लाह थे जिन्होंने फैसला किया कि कश्मीर सेक्युलर भारत के साथ रहेगा न कि मुस्लिम पाकिस्तान के साथ. महाराजा हरि सिंह जो अलग-थलग पड़ गए थे और यह सोचते हुए कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है पाकिस्तान चले गए होते. चाहे भाजपा को अच्छा लगे या नहीं, चाहे अमित शाह को अच्छा लगे या नहीं, लेकिन आप दो घटनाओं को अलग नहीं कर सकते. कश्मीर भारत के साथ शेख अब्दुल्लाह और नेहरू की वजह से है. कश्मीर समस्या भी नेहरू की वजह से है, और दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आप यह नहीं कह सकते कि अगर नेहरू नहीं होते तो कश्मीर मसला नहीं होता. जी हां, बिलकुल सही, कोई मसला नहीं होता क्योंकि ऐसे में कश्मीर पाकिस्तान में चला गया होता. भाजपा को दोबारा इतिहास पढ़ना चाहिए और अपना स्टैंड साफ़ करना चाहिए. जहां तक हम समझते हैं आरएसएस और भाजपा का स्टैंड मुस्लिम मुक्त भारत का है. अगर ऐसा है तो उन्हें साफ़-साफ़ कहना चाहिए कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ चले जाना चाहिए. लेकिन वे वहां सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए कई क़दम उठा रहे हैं ताकि कश्मीरियों को अपने में कैसे सम्मिलित किया जाए. मेरे ख्याल से भाजपा के नीति निर्माताओं के बीच बड़ी भ्रान्ति फैली हुई है. मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस उनका मार्गदर्शन कर रहा है या नहीं. लेकिन अरुणाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में उनकी चालों से एक बात साफ़ हो रही है कि वे कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य जितना हो सके राज्य सरकारों को अपने हिस्से में कर लिया जाए, सिद्धांत और नीति से कोई मतलब नहीं है.

एक और घटना जो समाचारों में है. अब मॉल और रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रहेंगे. एक बार फिर हम पश्चिम की नक़ल कर रहे हैं. मेरे ख्याल में अमेरिका का. भारत को अपनी संस्कृति के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. शहरों में भोजनालय पहले से देर रात तक खुले रहते हैं, लेकिन हमें इस मामले में धीमी रफ़्तार से आगे बढ़ना चाहिए. मुझे नहीं पता कि आखिर इसका मकसद क्या है? क्या यह राजस्व इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है या रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए? जो भी हो सरकार को अपनी नीति साफ़ करनी चाहिए. आज तक एनडीए सरकार का लेखा-जोखा तैयार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वे यूपीए सरकार की स्कीमों को ही जारी रखे हुए हैं. कुछ के नाम बदलकर और कुछ पुराने नामों के साथ (जैसे मनरेगा). मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप को गरीबों, दबे-कुचले, बेरोजगारों, खेतिहर मजदूरों के लिए काम करना है तो कुछ ऐसे काम हैं जो कांग्रेस भी अपने तरीके से कर रही थी, भाजपा यह काम अपनी सोच के हिसाब से कर सकती है. लेकिन यह कहना कि जनधन योजना, कृषि बीमा क्रान्तिकारी फैसले हैं, सही नहीं है. ये ऐसी स्कीमें हैं जो काफी पहले से चल रही हैं, और बेशक इनमें सुधार की ज़रूरत है. अगर भाजपा इन स्कीमों को बेहतर बनाती है, खास तौर पर किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए तो उसका स्वागत होना चाहिए.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने अपनी मंज़ूरी दे दी. लेकिन यह अपेक्षित था. मैं नहीं समझता कि किसी सरकार के पास इसको लेकर अधिक विकल्प होते हैं. क्योंकि वेतन आयोग अनेक प्रक्रियाओं से गुज़रकर अपनी सिफारिशें पेश करता है. अगर सरकार उसमें किसी तरह की कटौती करने की कोशिश करेगी तो इससे सरकारी कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ेगी. बेशक इसमें पैसे खर्च होंगे, लेकिन इसके लिए बजट का आवंटन कर इसका खयाल रखा जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

पैरवी नहीं तो जज नहीं

कवर स्टोरी-जजों की नियुक्ति के लिए बनी सूची में न्यायाधीशों के बेटों और रिश्तेदारों की भरमार, पैरवी में है दम, जज बनेंगे हम (13 जून- 19 जून 2016) पढ़ा. प्रभात रंजन दीन ने बिल्कुल सही कहा है कि जब न्यायाधीश ही अपने नाते-रिश्तेदारों और सरकार के प्रतिनिधि-पुत्रों को जज नियुक्त करेंगे तो संविधान का संरक्षण कैसे होगा? जब न्यायालय में यह गोरखधंधा चल रहा है, तो बाकी जगहों की बात ही अलग है. सरकारी नौकरी हो, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति का मामला हो या कोई और सच्चाई तो ये है कि हर जगह पैरवी पर ही नियुक्तियां हो रही हैं. यह एक सच्चाई है जिसे झुठा साबित नहीं किया जा सकता है. देश की जनता इन पैरवी वाले जजों से न्याय की उम्मीद भला कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से देश की जनता को उम्मीद है. अगर सरकार लापरवाही बरतती है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान हमेशा सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर उसे अपना उत्तरदायित्व याद दिलाने का काम करती है. अब लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट को इन पैरवी वाले जजों की नियुक्ति पर भी बोलना चाहिए.

-सौरभ कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

पुलिस की बर्बरता

आलेख-शांति दूतों पर पुलिसिया हमला (13 जून-19 जून 2016) पढ़ा. लेखक ने इस आलेख के जरिए बताया है कि अरुणाचल प्रदेश के हालात यहां से कितने जुदा हैं. पुलिस की बर्बरता एक बेहद गंभीर मसला है. अरुणाचल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाईं और आंदोलनकारियों की बर्बर तरीके से पिटाई की गई. अरुणाचल प्रदेश की पुलिस हो या कहीं और सभी जगहों की पुलिस का यही हाल है. हर जगह की पुलिस की बर्बरता न्यूज चैनलों और अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन पूर्वोत्तर की एक भी खबरें न न्यूज चैनलों पर दिखती है और न ही अखबारों में. अरुणाचल प्रदेश में लोगों के हितों के खिलाफ निजी कंपनियां और सरकारी महकमे काम करे रहे हैं जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने आवाजें उठाईं, तो उन्हें पुलिस की लाठियां खाने को मिलीं. साथ ही लाठियों के बल पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई. आखिर वहां की जनता अपना दर्द किससे कहे? वहां के लोगों की न केंद्र सरकार सुनती है और न ही राज्य सरकार. वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार को मीडिया भी नहीं दिखाता.

-बिमलेश राय, *मोतिहारी, बिहार.*

आप का विवादों से नाता

केजरीवाल सरकार हमेशा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर किसी न किसी बहाने हमला करती रहती है. अरविंद केजरीवाल ने आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्ति किया था, जो लाभ के पद के दायरे में आता है. यह संसदीय सचिव भले ही सैलरी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑफिस और गाड़ियों का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि वह कोई लाभ नहीं ले रहे हैं. आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लगा कि उन्होंने गलती कर दी है. इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा में संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने से संबंधित विधेयक पास कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने सरकार के इस विधेयक को मंजूरी देने से इंकार कर दिया. अब इस विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी न मिलने की वजह से आप के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है. केजरीवाल कई राज्यों और पार्टियों को गिना रहे हैं कि उन्होंने भी संसदीय सचिव रखे हैं और दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी संसदीय सचिव रखा था. अब इस मामले में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को फैसला लेना है और इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती. केजरीवाल और उनकी पार्टी का विवादों से नाता है.

-गौरव वर्मा, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

ध्रुवीकरण की कोशिश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं. इस समय कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें आ रही हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलग-अलग अखबारों और न्यूज चैनलों में पलायन को लेकर भी अलग-अलग खबरें मिल रही हैं. इससे पहले देश में राम मंदिर का मुद्दा भी खूब गर्म हुआ था. उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम है. इसलिए राम मंदिर और कैराना मुद्दे को हवा दी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता राम मंदिर को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, जैसे दिसंबर, 2016 में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी वगैरह-वगैरह. इसके बाद अब कैराना को लेकर भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं. भाजपा के सांसद हुकम सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की और हिंदुओं के पलायन की बात कही. राम मंदिर और कैराना को लेकर आजकल जो भी देश में हो रहा है, वह केवल चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. लेकिन, भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि अब देश की जनता गोमांस, राम मंदिर या कैराना जैसे मुद्दों के झांसे में नहीं आने वाली है.

-विनीत यादव, *दानापुर, बिहार.*

निष्पक्ष होकर कार्य करें

आलेख-काम कम, शोर ज्यादा (27 जून- 03 जुलाई 2016) पढ़ा. कमल मोरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि स्मृति ईरानी केवल अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए तेज स्वर में बोल रही हैं. स्मृति ईरानी आज कल कहीं भी सभा करती हैं, तो विपक्षी पार्टियों पर खूब हमला करती हैं. अगर हम उनके लोकसभा और राज्यसभा में दिए गए भाषणों को सुनें, तो वह काफी तेज स्वर में बोलती हुई दिखती हैं. चाहे जेएनयू का मामला हो या कोई अन्य, उस पर वे संसद चिल्लाती ही नजर आईं. यह सही है कि स्मृति ईरानी बहुत जल्दी आगे निकलने की होड़ में हैं. वे चाहती हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए. स्मृति ईरानी और उनका मंत्रालय सरकार बनने के बाद से ही हमेशा विवादों में रहा है. बार-बार उनपर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगता रहा है. संसद में गलत तथ्य प्रस्तुत करने का भी उनपर आरोप लगा है. स्मृति ईरानी को निष्पक्ष होकर काम करने की जरूरत है. शिक्षा और छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए.

-संजय सिंह नेगी, *देहरादून, उत्तराखंड.*

कैसे जीतेगी कांग्रेस

जब तोप मुकाबिल हो-कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति (27 जून- 03 जुलाई 2016) पढ़ा. इसमें संतोष भारतीय लिखते हैं कि राहुल गांधी काम पर कब होते हैं, इस सवाल का कभी जनता को जवाब नहीं मिलता. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी छुट्टी पर हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, सपा और बसपा सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस को इसकी कोई चिंता ही नहीं है. कांग्रेस शायद ऐसा सोच रही है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उसे बिना किसी मेहनत के उत्तर प्रदेश की सत्ता दिला देंगे. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा है और वे अपनी समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के ऊपर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी है, लेकिन राहुल गांधी का कोई पता नहीं है. भाजपा ने चुनावी सभा शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर सक्रिय हो गई है. सपा और बसपा भी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस प्रशांत किशोर के हाथ में चुनावी कमान थमाकर शांत बैठी हुई है. कांग्रेस बिहार में नीतीश के सहारे सीटें जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन असम में उसकी करारी हार हुई. कांग्रेस को पिछले चुनावों में हुई हार से सबक लेने की जरूरत है.

-नरेंद्र कुमार, *गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अब ख़ाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई...

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज है. समाजवादी पार्टी में घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है. ऐसे में अखिलेश यादव को नज़्में याद आने लगी हैं. इसी बीच उन्होंने सार्वजनिक मंच से मेहंदी हसन की ग़ज़ल की एक लाइन भी सुना डाली कि मोहब्बत में जुदाई का भी बहुत स्थान है. किससे जुदाई का? शायद अपने सगे चाचा शिवपाल सिंह यादव से जुदाई का. पारिवारिक तनाव भी ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं, जिनकी मिसाल देते हुए मन हिचकिचाता है. अखिलेश यादव का बचपन और जवानी के शुरुआती दिन जब वे पढ़ाई कर रहे थे, शिवपाल सिंह यादव के घर पर ही ज्यादा बीता. उनके करीबी लोग बताते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के घर पर खासकर उनकी पत्नी और बच्चों से अखिलेश यादव का बहुत ज्यादा अपनापन था. लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों के घरों की दूरी जो सौ गज के आस-पास रही होगी, बढ़ते-बढ़ते सौ किलोमीटर में तब्दील हो गई.

परिवार के सभी सदस्य राजनीति में अपना-अपना प्रथम स्थान तलाश रहे हैं. मुझे लगता है कि मुलायम सिंह असहाय होकर अपने परिवार के हर सदस्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के परिणामस्वरूप होने वाले टकराव को देख रहे हैं. सिर्फ परिवार में धर्मेंद्र यादव ऐसे नजर आए, जिन्हें लेकर अभी तक कोई सरगोशी बाहर नहीं आई है. दूसरा नाम तेजप्रताप यादव का भी ले सकते हैं, लेकिन यह स्थिति कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. सपाई तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन वही सपाई आज तमाशा देखने की मुद्रा में हैं. ऐसे मेहंदी हसन की ही ग़ज़ल की लाइन दोहराता हूं ...अब तो ख़ाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई.

मायावती के यहां से लोगों के जाने का सिलसिला जारी है. आरके चौधरी मायावती को छोड़ गए. शायद अभी कुछ और लोग छोड़कर जाएं. उनके जाने से मायावती कमजोर होंगी या नहीं, फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता. लेकिन लोगों को लगता है कि शायद मायावती थोड़ी कमजोर होंगी.

सबसे बड़ी परेशानी कांग्रेस की है. शीला दीक्षित को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा कांग्रेस में शुरू हो गई है. कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अगला प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाए या प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री को बिना हटाए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे और कैंपेन कमेटी का सर्वेसर्वा किसी और को घोषित करे. स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की होड़ में काफी ताकत लगा रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि प्रदेश में युवा चेहरा उन्हीं का है, जो दल को जीत दिला सकता है और राहुल गांधी का समर्थन भी उनकी तरफ रहेगा. पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं. लेकिन प्रियंका गांधी की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी भी कीमत पर उनको राजनीति में नहीं आने देना चाहती हैं. हो सकता है इसपर कोई समझौता हो कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करेंगी. प्रियंका गांधी, शीला दीक्षित, जितिन प्रसाद और एक भूला-बिसरा नाम संजय सिंह का है, जिसे लेकर कांग्रेसियों में उत्साह है. पर शायद संजय सिंह को गांधी परिवार अभी क्षमा करने के मूड में नहीं दिखाई देता. कांग्रेस हाईकमान का संजय सिंह से कोई कम्युनिकेशन या संवाद नहीं है. आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान माने जाने वाले राहुल गांधी देश में नहीं हैं, विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं. प्रशांत किशोर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़े हुए हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को एक नया रास्ता दिखा दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसे ही मैनेजर्स की एक टीम उत्तर प्रदेश में भाजपा को सक्रिय करने के लिए अपने साथ ले ली है. समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अभी तक मैनेजर्स के हाथ में नहीं गई हैं. पर हो सकता है समाजवादी पार्टी भी अंतत: राजनीतिक प्रबंधकों के हाथ में पहुंच जाए. ये राजनीतिक प्रबंधक रणनीति बनाते हैं. किस नेता को कब और कहां क्या बोलना है, वे तय करते हैं. किस कार्यकर्ता को किन क्षेत्रों में लगना है, ये बताते हैं. कुल मिलाकर अब वे सारे काम करते हैं जो पार्टी अध्यक्ष को करना चाहिए. यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार होता दिख रहा है.

नीतीश कुमार का अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई रोल नहीं है. उनकी दो सभाएं हो चुकी हैं और 16 जुलाई को उनकी सभा इलाहाबाद में है. बनारस और मिर्जापुर में हुई उनकी दोनों सभाओं में 10 से 15 हजार के आस-पास भीड़ थी, जो बेहतर मानी जा सकती है. नीतीश की सबसे बड़ी दुविधा उनका अपना संगठन है. नीतीश कुमार के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जिसका मुकाबला उत्तर प्रदेश के स्थापित नेताओं, चाहे वे मुलायम सिंह हों, मायावती या फिर भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह से किया जा सके.

जब तक नीतीश कुमार किसी ऐसे चेहरे को नहीं ढूंढ़ लेते, जिसमें उनका सामना करने की ताकत हो या जो वैचारिक आधार पर अपनी वाणी से मुलायम सिंह, मायावती और राजनाथ सिंह का मुकाबला तर्कों से कर सके, तब तक उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई संभावना नजर नहीं आती. नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए उनके हिस्से में सिर्फ कैंपेन करना आने वाला है. उनकी पार्टी में सिर्फ वे लोग हैं, जिन्होंने पिछले दस या पंद्रह सालों में पार्टी में कुछ नहीं किया. इस चुनौती का मुकाबला अगर नीतीश कुमार जुलाई खत्म होते-होते नहीं कर पाते, तो फिर अगर कोई गठजोड़ हुआ, जिसकी पूरी संभावना है, वे कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे. हालांकि कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे देखते ही लोग कहें कि ये चेहरा उनकी समस्याओं को हल कर पाएगा. अभी तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का चेहरा शीला दीक्षित होंगी, कैंपेन कमिटी के चेयरमैन संजय सिंह होंगे और प्रियंका गांधी कैंपेन करेंगी. लेकिन अगर प्रियंका या राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ अभी से हाथ नहीं मिलाते तो उनकी सीटों की संख्या 10 से 15 के बीच रह जाएगी. इस स्थिति में मायावती 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगी. अब भी उत्तर प्रदेश में मायावती, भारतीय जनता पार्टी, मुलायम सिंह और कांग्रेस यही क्रम दिखाई देता है. यद्यपि सपा के कई सांसदों ने बताया कि मायावती पैसे देकर ये हवा फैला रही हैं कि सपा तीसरे नंबर पर आने वाली है. समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति का आकलन ईमानदारी से नहीं कर पा रही है. एक बार ये लगा था कि शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी मिलते ही समाजवादी पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ेगी और चोट करेगी, लेकिन शिवपाल की हैसियत खुद उनकी पार्टी ने घटा दी.

> उत्तर प्रदेश के तिलिस्म में सबसे नीचे के पायदान पर नीतीश कुमार का दल है, जो योजनाएं बनाते हुए यह भूल जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव भी बिहार के चुनाव में कैंपेन करने गए थे. तब सारे उत्तर प्रदेश के मंत्री और कार्यकर्ता बिहार में लग गए थे, लेकिन उनका कोई भी प्रचार वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाया. ऐसा ही उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ होता दिख रहा है. बिहार के लोग, बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनी हुई जगहों पर लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग कहीं नहीं हैं.

यूपी के तिलिस्म में सबसे नीचे के पायदान पर नीतीश कुमार का दल है, जो योजनाएं बनाते हुए यह भूल जा रहा है कि मुलायम भी बिहार के चुनाव में कैंपेन करने गए थे. तब यूपी के सारे मंत्री और कार्यकर्ता बिहार में लग गए थे, लेकिन उनका कोई भी प्रचार वोट के रूप में तब्दील नहीं हो पाया. ऐसा ही यूपी में नीतीश कुमार के साथ होता दिख रहा है. बिहार के लोग, बिहार के कार्यकर्ता, बिहार के मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनी हुई जगहों पर लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग कहीं नहीं हैं. नीतीश के सामने यह खतरा है जिसे वे कभी समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी नेता अपने सामने आने वाले खतरे को देखना ही नहीं चाहता. वो खतरा है कि उत्तर प्रदेश में घूमेंगे, भीड़ होगी और वे घूमकर वापस बिहार चले जाएंगे.

शायद यूपी का चुनाव भाजपा के लिए वाटरलू साबित हो सकता है, कांग्रेस और मुलायम के लिए भी साबित हो सकता है. कौन अपने साथ विधायकों की कमी को पूरा कर सकता है, ये रणनीति देखने लायक होगी. सवाल है कि जिस तरह मुलायम को अनुमान से ज्यादा यूपी में सीटें मिलीं, क्या इस बार मायावती को अनुमान से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं. अगर ऐसा है तो यूपी तमिलनाडु के रास्ते पर चल पड़ेगा, जहां बाकी लोग समझौते की आस में बैठे रह जाएंगे और या तो बसपा या सपा सत्ता के नजदीक पहुंच जाएगी. ■

editor@chauthiduniya.com

जनमत संग्रह

बिखर सकता है ग्रेट ब्रिटेन

मेघनाद देसाई

यूरोपीय यूनियन से अलग होने के निर्णय से पूरी दुनिया के साथ सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश यूनाइटेड किंगडम के निवासी भी हैरान हैं. यूनाइटेड किंगडम पिछले 43 साल तक यूरोपीय यूनियन (ईयू) से किसी न किसी तरह से जुड़ा था. हालांकि ब्रिटेन पहले से ही एकल मुद्रा और सीमा रहित यूरोप से खुद को अलग रखे था.

जनमत संग्रह किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने का एक विशेष जरिया होता है. किसी आम चुनाव में कई दल मैदान में होते हैं, जिसमें जीतने और हारने का फैसला सबसे अधिक सीट हासिल कर होता है. इसमें एक तिहाई वोट लेकर कोई पार्टी भारी बहुमत हासिल कर सकती है. जनमत संग्रह में 'हां' या 'ना' में जवाब देना होता है, लिहाज़ा इसमें कोई उलझाव नहीं होता. इसमें जीत और हार का अंतर बहुत छोटा होता है, आम तौर पर चार प्रतिशत से भी कम. लेकिन यहां फैसला अपरिवर्तनीय होता है.

जनमत संग्रह की बहस ने उदारवादी और कॉस्मोपॉलिटन लोगों को वैसे लोगों से अलग कर दिया था जो खुद को अशक्त और विकास की धारा में पीछे छूट गया समझते थे. जहां एक तरह यूरोपीय यूनियन में बने रहने की वकालत करने वाला ग्रुप यूनियन छोड़ने से उत्पन्न विपरीत परिणामों की बात कर रहा था, वहीं बाहर जाने की वकालत करने वाला समूह यह कह रहा था कि यूनाइटेड किंगडम का अपने आंतरिक मामलों पर नियंत्रण कमज़ोर होता जा रहा है, इसलिए उन्हें अपनी आज़ादी पुन: हासिल कर लेनी चाहिए. एक ऐसे देश के लिए जो यूरोप में सबसे प्राचीन पॉलिटी (शासन विधि) वाला देश है, उसके अन्दर ऐसी सोच हैरान करने वाली थी. यह विचार कि जब कोई राष्ट्र किसी बहुराष्ट्रीय संघ से जुड़ता है तो अपनी आज़ादी खो देता है, आसानी से गले नहीं उतरती. लेकिन आख़िरकार यह संदेश जनता ने दिया है. वे अपने देश में ईयू से बड़े पैमाने पर हो रहे अप्रवासन से चिंतित थे. इस अप्रवासन को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि श्रमिकों की मुक्त आवाजाही ईयू का बुनियादी सिद्धांत है. ऐसा लगता है कि ईयू अपने संस्थानों, नीतियों और नियमों की तकनीकी शब्दजाल से अवगत ही नहीं था.

> ईयू की संसद ने ब्रिटेन की जनता को कभी अपना समझा ही नहीं. काफी समय तक ब्रिटेन का ईयू से अलग होने से संबंधित सवाल पूछा जाता रहेगा-क्या यह ग्रेट ब्रिटेन के लंबे इतिहास का नतीजा है? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन का दुनिया पर लंबे समय तक वर्चस्व रहा और जिसके पास यूरोप के शक्ति संतुलन की कुंजी थी. या एक आइलैंड देश की अलग-थलग रहने और आज़ादी की अपनी अनूठी भावना ने ऐसा किया. या फिर हालिया मंदी के दौर ने गरीब लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और अमीर आगे निकल गए इस कारण लोग ईयू से अलग होना चाहते थे? इस जनमत संग्रह को 'असली लोगों की जीत' के रूप में दिखाया जा रहा है. दरअसल यह एक अतिशयोक्ति है क्योंकि 48 प्रतिशत लोग जिन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया क्या वे नकली लोग थे?

ईयू की संसद ने ब्रिटेन की जनता को कभी अपना समझा ही नहीं. काफी समय तक ब्रिटेन का ईयू से अलग होने से संबंधित सवाल पूछा जाता रहेगा-क्या यह ग्रेट ब्रिटेन के लंबे इतिहास का नतीजा है? क्या यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन का दुनिया पर लंबे समय तक वर्चस्व रहा और जिसके पास यूरोप के शक्ति संतुलन की कुंजी थी. या एक आइलैंड देश की अलग-थलग रहने और आज़ादी की अपनी अनूठी भावना ने ऐसा किया. या फिर हालिया मंदी के दौर ने गरीब लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और अमीर आगे निकल गए इस कारण लोग ईयू से अलग होना चाहते थे? इस जनमत संग्रह को 'असली लोगों की जीत' के रूप में दिखाया जा रहा है. दरअसल यह एक अतिशयोक्ति है क्योंकि 48 प्रतिशत लोग जिन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया क्या वे नकली लोग थे?

जनमत संग्रह का यह नतीजा ब्रिटेन की राजनीति को कई पीढ़ियों तक प्रभावित करेगा. ईयू से अलग होने के जनमत संग्रह की मांग कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से उठी थी. इस पार्टी में यूरोप को लेकर 1990 के बाद से ही दरार पैदा हो गई थी. यह वही दौर था जब मार्गरेट थैचर पार्टी नेतृत्व की लड़ाई हार गई थीं. यह भी आशंका जताई जा रही है कि एक दो साल में कंजर्वेटिव पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगी. कैमरन ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया है. पार्टी जिसे भी अपना नया नेता चुनेगी वे उसे अपनी कुर्सी सौंप देंगे. बोरिस जॉनसन को पार्टी का नया नेता चुने जाने की प्रबल सम्भावना है. नए नेता के साथ कैबिनेट में भी बदलाव होगा.

यूनाइटेड किंगडम के सामने उसकी एकता एक बड़ी गंभीर समस्या है. 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. जहां तक यूरोपीय यूनियन के जनमत संग्रह का सवाल है तो इंग्लैंड ने निर्णायक तौर पर इससे बाहर जाने का फैसला लिया, जबकि स्कॉटलैंड ने ईयू में बने रहने की राय ज़ाहिर की. लिहाज़ा स्कॉटलैंड की आज़ादी की मांग एक बार फिर उठ सकती है. उत्तरी आयरलैंड भी यूरोपीय यूनियन में बने रहना चाहता है. चूंकि उत्तरी आयरलैंड की सीमा आयरिश रिपब्लिक से मिलती है इसलिए दोनों आयरलैंड के एकीकरण की मांग के लिए आंदोलन शुरू हो सकता है, जो ऐतिहासिक होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

मध्यप्रदेश में शालेय शिक्षा का परिदृश्य अब तेजी से बदल रहा है। पिछले 7-8 वर्ष स्कूली शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इस अरसे में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही अधोसंरचना को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बच्चे खूब पढ़ें और आगे बढ़ें मंशा के अनुरूप राज्य में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचारों को अपनाया गया। बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद सृजित हुए और स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करवाने और उनके बौद्धिक एवं शारीरिक विकास की ओर भी राज्य सरकार ने ध्यान दिया। राज्य सरकार ने जहाँ एक ओर शिक्षा के नये कानून का पालन करवाया, तो दूसरी ओर स्कूल चलें हम अभियान जैसे कारगर उपायों को भी गति दी।

प्रदेश में स्कूली शिक्षा

बदलते आयाम

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

राज्य शासन द्वारा 9 विभाग की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के मूल स्वरूप, छात्रवृत्ति की दरों और पात्रता के मापदण्ड में परिवर्तन नहीं करते हुए केवल विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों को समेकित छात्रवृत्ति योजना के रूप में लागू किया गया है। प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख शासकीय/अशासकीय विद्यालय की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत लगभग एक करोड़ 84 लाख विद्यार्थियों के समग्र पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की डाइस कोडवार शाला से मेपिंग की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति ऑनलाइन स्वीकृत कर सीधे उनके खाते में भेजी जायेगी।

इस योजना में विद्यार्थियों को एक ही बार आवेदन तथा जाति प्रमाण-पत्र को सत्यापित करवाना होगा। भविष्य में पाठ्य-पुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण योजना समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। इसमें अब तक 1.83 करोड़ में से 1.33 करोड़ विद्यार्थियों की मेपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 80 लाख पात्र विद्यार्थी में से 54 लाख के लिये 294 करोड़ की छात्रवृत्ति की ऑनलाइन स्वीकृति भी दी जा चुकी है। हितग्राहियों के खाते में लगभग 102 करोड़ 65 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। पूर्व प्रक्रिया से भी 100 करोड़ का भुगतान किया गया है। इकलौती प्रतिभावान बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिये कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने एवं कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जा रही है।

उत्कृष्ट विद्यालय

गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड पर स्थापित एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जो एक श्रेष्ठ विद्यालय के बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये अपेक्षित है। उत्कृष्ट विद्यालयों में सुसज्जित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सामग्री, क्रीड़ांगण, कम्प्यूटर तथा अनुभवी एवं सुयोग्य शिक्षक तथा प्राचार्य जैसे भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं। वर्तमान में 41 जिला एवं 194 विकासखण्ड मुख्यालय पर उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिला-स्तर पर 9 तथा विकासखण्ड-स्तर पर 79 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं। जिला मुख्यालयों के उत्कृष्ट विद्यालयों में 47 हजार 890 विद्यार्थी हैं। वर्ष 2013-14 में जिला-स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 92.39 तथा 90.8 प्रतिशत रहा है।

स्कूल भवन

पंचवर्षीय योजना में विभिन्न जिलों में 400 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन, प्रति भवन 1.23 करोड़ की लागत से निर्माण की सहमति योजना आयोग से प्राप्त की गई है। वर्ष 2012-13 में 37 शाला भवन लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) और शहडोल एवं नीमच, सागर, बुरहानपुर, हरदा तथा श्योपुर के डीईओ कार्यालय भवन निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग को नियुक्त किया गया है। खण्डवा, खरगोन, विदिशा, मुरैना एवं दमोह में जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर प्री-फेब तकनीक से मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण की पहल भी की गई।

गुणवत्ता सुधार

शिक्षक प्रशिक्षकों को बच्चों द्वारा सीखने की प्रक्रिया की समझ बढ़ाने के लिये हैदराबाद तथा क्षमता संवर्धन पर जोर देने के लिये नामी संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रत्येक जिले द्वारा आवश्यकताओं एवं भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए जिले के अकादमिक गुणवत्ता सुधार के लिये योजना लागू की गई है। शिक्षकों के लिये आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। शैक्षणिक उपलब्धियों एवं शालेय व्यवस्थाओं के सही मूल्यांकन के लिये प्रतिभा-पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुणवत्ता सुधार के लिये 16 हजार 5 प्राथमिक शालाओं में गतिविधि आधारित शिक्षण तथा 14 हजार 280 माध्यमिक शालाओं में सक्रिय अधिगम प्रविधि कार्यक्रम चलाया गया है। कुल 10 हजार 900 मिडिल शालाओं में गणित तथा विज्ञान किट की व्यवस्था की गई है।

शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिये पहली बार अभियान

राज्य शासन द्वारा शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिये विगत एक जून से चलाये जा रहे अभियान का लाभ लाखों शिक्षकों को मिल रहा है। अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। अभियान में अब तक संकुल एवं जिला स्तर तक प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की गई है। संकुल स्तर पर संकुल प्राचार्य तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निराकरण करवाया गया है। अभियान में संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर 20 अगस्त तक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण हुआ। इसके बाद संचालनालय स्तर पर भेजे जाने वाले प्रकरणों का निराकरण आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा किया गया। शासन स्तर पर भेजे जाने वाले प्रकरणों का निराकरण 15 सितम्बर तक अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा किया जायेगा। शासन द्वारा शिक्षकों के लंबित प्रकरणों एवं समस्याओं को त्वरित गति से निराकृत किये जाने के निर्देश सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर को दिये गये हैं। जिलों में अभियान को लेकर की गई कार्यवाही की निगरानी भी जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है। शिक्षकों की जिन प्रमुख लंबित समस्याओं का निराकरण करवाया जा रहा है, उनमें पदोन्नति, क्रमोन्नति तथा वेतन वृद्धि से संबंधित समस्याएँ, वरिष्ठता/पदक्रम सूची और वेतन निर्धारण से संबंधित कठिनाइयाँ, सेवानिवृत्ति स्वत्वों के लंबित प्रकरण, सामान्य भविष्य निधि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश स्वीकृति और निलम्बन अवधि के निराकरण से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं। अभियान के दौरान संकुल, जिला, संभाग, राज्य स्तर पर प्राप्त प्रकरणों की पंजी संधारित की गई है। इसमें प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण, आवेदन प्राप्ति की तिथि एवं निराकरण तथा सक्षम स्तर को प्रकरण भेजने की तिथि का उल्लेख किया गया है।

'स्कूल चलें हम' अभियान

प्रतिवर्ष बच्चों को स्कूल तक लाने के लिये "स्कूल चलें हम" अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में शालाओं में दर्ज करवाने के साथ-साथ उनकी नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी सुनिश्चित करना है। यह अभियान चार चरण में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतन कर द्वितीय चरण में नामांकन अभियान चलाया गया। तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण शिक्षा की गुणवत्ता पर केन्द्रित रहेगा। इस वर्ष अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक तीन लाख से अधिक मोटिवेटर (प्रेरक) पंजीकृत हो चुके हैं। अभियान से जन-प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं, शिक्षाविदों को जोड़ा गया है। अन्य गतिविधियों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 94 लाख बच्चों को दो जोड़ी गणवेश 400 रुपये के मान से राशि दी गई।

शालाओं का उन्नयन

प्रदेश में विगत 5 वर्ष में 1592 मिडिल स्कूल का हाई स्कूल तथा 840 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया गया। उन्नयन में ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया। इस वर्ष 50 माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किया जा रहा है। इस वर्ष 100 नये हायर सेकेण्डरी स्कूल भी खोले जा रहे हैं।

शिक्षकों का नियोजन

शिक्षकों की कमी की पूर्ति की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में 42 हजार 88 संविदा शाला शिक्षक की भर्ती की गई। प्रथम काउंसलिंग में 32 हजार 459 तथा द्वितीय काउंसलिंग में 9,629 पद पर संविदा शाला शिक्षक नियुक्त हुए।

पाठ्यपुस्तक वितरण

शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करवाने की योजना में वर्ष 2012-13 में 55 करोड़ एवं 2013-14 में 58 करोड़ रुपये व्यय कर छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। जिन पुस्तकों का प्रकाशन पाठ्य-पुस्तक निगम नहीं करता, उन्हें प्राचार्य के माध्यम से क्रय करवाकर छात्र-छात्राओं को वितरित किया जा रहा है।

निःशुल्क साइकिल

एक गाँव से दूसरे गाँव में विद्यालय में अध्ययन के लिये जाने वाले कक्षा 9वीं के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दी जा रही है। वर्ष 2009-10 से प्रारंभ इस योजना में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में केवल छात्राओं तथा वर्ष 2011-12 से छात्र वर्ग को भी लाभान्वित किया गया चालू माली साल में 5 लाख 22 हजार 833 छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हुए।

प्रोत्साहन योजना

शासकीय स्कूलों की कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय के लिये 25 हजार प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009 से दी जा रही है। इससे वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक 9544 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री की चौहान द्वारा वर्ष 2013 में की गई घोषणा के अनुसार पिछले दो वर्ष में 7352 अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिला।

मॉडल स्कूल

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 201 विकासखण्ड में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये 201 मॉडल स्कूल में 31 हजार विद्यार्थी दर्ज हुए हैं। मॉडल स्कूल के लिये 297 लाख रुपये के भवन निर्मित किये जा रहे हैं।

शारीरिक, बौद्धिक शिक्षा

जिला मुख्यालयों के हायर एवं हाई सेकेण्डरी स्कूलों की छात्राओं को जूडो-कराटे एवं ताईक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। वीर बालाकार द्वारा अंग्रेजों को फेर में लेकर समुद्र पार कर जेल से मुक्त होने के साहसिक प्रयास की स्मृति में वर्ष 2011 से बालक-बालिकाओं की तैराकी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिये कक्षा 8 से 12 तक शालेय प्रतियोगिता सभी विद्यालयों में प्रतिवर्ष जून में की जा रही है। वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रदेश के बालक-बालिकाओं द्वारा 43 स्वर्ण, 45 रजत एवं 72 कांस्य-पदक प्राप्त कर मेडल टेली में आठवाँ स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष ताईक्वांडो, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोप स्कीपिंग, खो-खो, कबड्डी तथा टेनिस बॉल क्रिकेट की राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिताएँ करवायी गईं।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

प्रदेश के 1490 मदरसों को भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है। मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का भुगतान ई-बैंकिंग के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्व-शिक्षा अभियान से करवाया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के लिये 4440.84 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य-योजना स्वीकृत हुई है। अभियान में 17 हजार 851 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शाला में उन्नयन किया गया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

वर्ष 2010 से संचालित माध्यमिक शिक्षा अभियान में अभी तक स्वीकृत सभी 944 हाई स्कूल संचालित हैं। 944 हाई स्कूल भवन, 4178 विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय इत्यादि के रूप में स्वीकृत 28 हजार 925 कार्यों का 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इन स्कूलों के शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वीकृत 15 हजार 329 पद में से 13 हजार 896 शिक्षक की पदपूर्ति की गई है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की 66 हजार बालिकाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। कक्षा 9 से 12 के लिये 201 बालिका छात्रावास स्वीकृत हैं जिनमें लगभग 17 हजार बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। कक्षा 9वीं में इस वर्ष 16 जून से 50 विद्यालय में आई.टी. एवं सिक्युरिटी ट्रेड आरंभ किया गया है। प्रत्येक ट्रेड में सभी स्कूल में 25-25 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले 12 हजार 913 विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के सुविधा भत्तों का प्रदाय किया जा रहा है। अभियान में बालिका छात्रावास, आई.सी.टी., व्यावसायिक शिक्षा, आई.ई.डी.एस.एस. योजना को समाहित किया गया है। एकीकृत कार्य-योजना के लिये कुल 43824.26 लाख की स्वीकृति मिली है।

अन्य गतिविधियाँ

पाँचवीं पास करके छठवीं में पड़ोस के गाँव की शासकीय शाला में पढ़ने जाने वाले बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल के लिये 2300 रुपये प्रति साइकिल दिये जा रहे हैं। गत वर्ष 3 लाख 30 हजार से अधिक साइकिल वितरित की गईं। इसमें से 37 प्रतिशत अनुसूचित-जनजाति एवं 17 प्रतिशत अनुसूचित-जाति के बच्चे लाभान्वित हुए। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों की व्यवस्था से 49 हजार 601 बालिकाएँ लाभान्वित हो रही हैं। विकलांग बच्चों के लिये 58 छात्रावास संचालित हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। निःशक्त बच्चों को कक्षा 1 से 8 की पुस्तकें ब्रेल-लिपि में दी जा रही हैं।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी
D-77229/15

रोशन होता मध्यप्रदेश

प्रदेश भर में | 24 घंटे बिजली

कई योजना हैं किसानों के लिए

किसानों की सुविधा के लिये कई योजनाओं को लागू किया गया है। किसानों द्वारा स्वयं ट्रांसफार्मर लगाने की योजना 4 मई 2011 से लागू की गई है। जले खराब ट्रासफार्मर प्राथमिकता पर बदलने के लिये बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की सुविधा को शिथिल कर 25 प्रतिशत किया गया है। अस्थाई पम्प कनेक्शन होने पर जले खराब ट्रांसफार्मर बदलने में इस अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया है। पूर्व में अस्थाई तथा स्थाई पम्प कनेक्शन पर स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने अथवा अवधि समाप्त होने के बाद भी अस्थाई पम्प कनेक्शन चालू पाये जाने की स्थिति में मैदानी अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज किये जाते थे।

1700 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित होंगे

उत्पादन वृद्धि में बीजोपचार एवं बीज की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए शत प्रतिशत बीजोपचार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष 20 हजार सीड ट्रीटिंग ड्रम एवं स्पायरल ग्रेडर की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्यक्रम पर रुपये 45 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी। कृषकों को किराये पर उन्नत बड़े यंत्र सुगमता से उपलब्ध हो सके इसके लिये आगामी 5 वर्ष में निजी क्षेत्र के माध्यम से 1700 कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना के लिये 170 करोड़ की व्यवस्था की जायेगी। कम एवं अधिक वर्षा के प्रभाव से सोयाबीन एवं दलहनी फसलों को बचाने के लिए रिज फरो पद्धति का विस्तार किया जायेगा। इसके लिये प्रति वर्ष 50 हजार रिज फरो पंजी अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। जैविक प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कृषकों को 50 प्रतिशत तक प्रमाणीकरण शुल्क अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्र में बनेंगे 100 बलराम

समर्थन मूल्य पर खरीदी किये जाने वाले केन्द्रों पर प्रथम चरण में सौ सर्वसुविधायुक्त ग्रामीण बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक केन्द्रों अथवा बलराम केन्द्र,स्थान एक समाधान अनेक का विकास किया जाएगा। इसमें समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये इलेक्ट्रानिक तौल, भंडारण, पक्का प्रांगण, किसान गेस्ट हाउस बैंक, कृषि आदान एवं सूचना केन्द्र आदि की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन केन्द्रों की स्थापना के लिये राज्य सरकार प्रति केन्द्र अधिकतम 2.5 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवायेगी। इस तरह के केन्द्र भविष्य में प्रदेश के सभी ऐसे खरीदी केन्द्रों पर बनाये जायेंगे जहां स्थान उपलब्ध है। प्रमाणिक कृषि आंकड़े एकत्र करने की दिशा में भी शासन निरंतर प्रयासरत है। इससे प्रदेश की विकास योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी।

किसान होंगे प्रोत्साहित

फार्म मेकेनाइजेशन को प्रोत्साहित करने के लिये यंत्रदूत योजना का विस्तार 89 आदिवासी विकासखण्ड में किया गया है। प्रथम चरण में एक-एक गांव में योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया है। सिंचाई जल के अधिक से अधिक क्षेत्र में उपयोग करने के लिये ड्रिप, स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य माइक्रो मिशन में 5 वर्ष में इन उपकरणों को अनुदान पर उपलब्ध करवाने के लिये 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कोदो कुटकी, ज्वार, बाजरा फसलों के प्रसंस्करण के लिये स्थानीय स्तर पर 100 लघु उद्योग स्थापित करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश को रोशन करने के लिए नवीन ऊर्जा

मध्य प्रदेश देश ही नहीं सारे विश्व में ऊर्जा संकट के समाधान, दीर्घकालीन जीवन के लिये बेहतर पर्यावरण और इसके लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों के उपयोग तथा दोहन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम एक स्वतंत्र मंत्रालय की दिशा में पहल कर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का अप्रैलए 2010 में गठन किया। विगत तीन वर्ष में ग्रिड संयोजित अक्षय ऊर्जा स्रोत आधारित विद्युत उत्पादन के लिये लघु जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बॉयोमास ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये पृथक-पृथक नीतियां लागू की गई। इन नीतियों में विकास कों एवं निवेशकों के लिये अनेक प्रावधान किये गये। इनमें विद्युत शुल्क एवं उपकर में छूट बिलिंग दर में 4 प्रतिशत का अनुदान, तृतीय पक्ष विद्युत विक्रय के प्रावधान, 100 प्रतिशत बैंकिंग सुविधाएं कान्ट्रेक्ट डिमांड में कमी आदि के प्रावधान हैं। इन परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में इन स्रोतों से 474 मेगावाट विद्युत उत्पादित हो रही है, जो राज्य की कुल विद्युत क्षमता का 5.31 प्रतिशत है।राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से दिसम्बर, 2014 तक यह क्षमता बढ़कर 2500 मेगावाट होना संभावित है, जो राज्य की कुल उत्पादन क्षमता का 17 प्रतिशत होगी। नीतियों के अनुसार परियोजना आवंटन प्रक्रिया के प्रावधानों के अंतर्गत खुले आवेदन आमंत्रित किये गये। नीतियों को बेहतर पाते हुए निवेशकों एवं विकासकों से समर्थन स्वरूप प्रदेश में अधिक क्षमता के परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभाग के अंतर्गत 2550 मेगावाट क्षमता की 150 परियोजनाओं के क्रियान्वयन से लगभग 19 हजार 500 करोड़ का निवेश होना संभावित है।

क्र.	तकनीक	परियोजना	कुल क्षमता (मेगावाट)	कुल निवेश (करोड़ में)
1.	पवन ऊर्जा	45	1448	8688
2.	लघु जल ऊर्जा	46	153	1220
3.	सौर ऊर्जा	58	940	9400
4.	बायोमॉस ऊर्जा	1	12	66
	कुल	150	2553	19374

नवकरणीय ऊर्जा क्रय मापदंड के लिए सोलर इनर्जी पीपीए

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2012 में सोलर इनर्जी के मापदंडों की लक्ष्य पूर्ति करने के उद्देश्य से अनुबंध किए थे, जिसमें सोलर परियोजनाओं से 175 मेगावाट सोलर इनर्जी प्रदेश के लिए प्राप्त की जा रही है। वहीं इस वर्ष 100 मेगावाट सोलर इनर्जी के पावर परचेस एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किए गए हैं, जिनसे 19 से 24 माह के अंदर प्रदेश को बिजली प्राप्त होने लगेगी। नवकरणीय ऊर्जा क्रय मापदंड की पूर्ति करने की दृष्टि से 170 मेगावाट विंड इनर्जी के पावर परचेस एग्रीमेंट निष्पादित किए गए हैं।

रबी सीजन के लिए ठोस प्रबंधन

आगामी रबी सीजन में प्रदेश में बिजली की अधिकतम अनुमानित मांग 11,000 मेगावाट के लगभग होने की संभावना है। रबी सीजन में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लांग टर्म पावर परचेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली बिजली के साथ-साथ अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से बैंकिंग सिस्टम से बिजली प्राप्त करने के समुचित प्रबंध किए गए हैं।

ट्रांसमिशन लॉसेस पहुंचे 3 प्रतिशत तक

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अथक प्रयासों से ट्रांसमिशन लॉसेस वित्तीय वर्ष 2013-14 में घट कर 3.00 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए हैं, वहीं पारेषण प्रणाली की उपलब्धता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 98 प्रतिशत के निर्धारित मापदंड से अधिक 99.43 प्रतिशत तक है। पिछले वित्तीय वर्ष में ही कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता में 3412.5 एमवीए की वृद्धि की गई है, जो कि एमपी ट्रांसको के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक उपलब्धि है। कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन स्काडा प्रणाली की स्थापना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 132 केवी सब स्टेशन माढोताल, जबलपुर में स्काडा नियंत्रण कक्ष क्रियाशील कर ईस्ट डिस्ट्राम के कार्यक्षेत्र के सात इण्डायी सब स्टेशनों को सफलतापूर्वक संबद्ध कर दिया है। यहां यह बताना जरूरी होगा कि भविष्य में ट्रांसमिशन स्काडा प्रणाली की सहायता से सब स्टेशनों का रव-संचालन भी संभव हो सकेगा।

एटी एंड सी लॉसेस को कम करने के लिए आर-एपीडीआरपी

प्रदेश की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने अटल ज्योति योजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात विद्युत भार को दृष्टिगत रखते हुए प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य करना शुरू कर दिए हैं। इन कार्यों में नए सब स्टेशनों, 33 केवी लाइनों के निर्माण के साथ नए पावर ट्रांसफार्मरों की स्थापना महत्वपूर्ण है। एटी एंड सी लॉसेस को कम करने के लिए तीनों डिस्कामों में आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को पूर्ण हो जाने के पश्चात् बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बेहतर गुणवत्ता से बिजली सप्लाई संभव हो सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन देने के लिये नवीन पम्प कनेक्शन अनुदान योजना एक अप्रैल, 2011 से लागू की गई है। इसमें सीमांत कृषकों को वर्तमान में 5500 रुपये प्रति हार्स-पॉवर तथा अन्य को 8800 रुपये प्रति हार्स-पॉवर देना होता है। इस कार्य के लिये आवश्यक राशि में से डेढ़ लाख रुपये तक शेष राशि राज्य शासन द्वारा दी जा रही है। इस योजना में अक्टूबर, 2012 तक 20 हजार 142 स्थाई पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। इसके पूर्व की किसान महापंचायत घोषणा के अंतर्गत माँ 31 हजार से ज्यादा पम्प को विद्युत संयोजन प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2003-04 में 4 लाख 5 हजार अस्थाई कनेक्शन कृषि पम्प के लिये प्रदान किये गये थे। वर्ष 2011-12 में 10 लाख 72 हजार अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदान किये गये हैं, जो वर्ष 2003-04 की तुलना में 165 प्रतिशत अधिक है।

पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा श्रेष्ठ कार्य निष्पादन

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग के ताप विद्युतगृहों ने वर्ष 2013-14 में 69.27 प्रतिशत प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पीएएफ) अर्जित किया, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की 500 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक पांच ने अभी तक का सर्वाधिक 97.7 प्रतिशत पीएएफ प्राप्त किया। इसी यूनिट की विशिष्ट तेल खपत 0.28 मिली लीटर प्रति यूनिट रही, जो कि अभी तक की न्यूनतम वार्षिक तेल खपत है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट क्षमता की इकाई क्रमांक पांच ने भी अभी तक का सर्वाधिक 95.70 प्रतिशत पीएएफ अर्जित किया। इस यूनिट ने भी वार्षिक न्यूनतम विशिष्ट तेल खपत में रिकॉर्ड बनाया। यूनिट की तेल खपत 0.42 मिली लीटर प्रति यूनिट रही। पावर जनरेटिंग कंपनी, ताप बिजली की उत्पादन लागत दर में कमी लाने के उद्देश्य से ईंधन की बचत करने के उपायों पर गहनता से कार्य कर रही है। इन्हीं उपायों के क्रियान्वयन से वर्ष 2013-14 में विशिष्ट तेल खपत में 2.91 मिली लीटर प्रति यूनिट प्राप्त हुई। यह खपत पिछले वर्षों की तुलना में कम है। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के जल बिजली गृहों ने वर्ष 2013-14 में इतिहास में सर्वाधिक 3673.4 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 512.7 मिलियन यूनिट अधिक है। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को नई ताप बिजली परियोजनाओं की कोयला आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा सिंगरौली स्थित गोंदबहेरा में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस कोल ब्लॉक को विकसित करने का कार्य वर्ष 2013 से प्रारंभ हो गया है।

जले तथा खराब ट्रांसफार्मर बदलने एसएमएस योजना

जले तथा खराब ट्रांसफार्मरों को वरीयता क्रम के साथ-साथ निर्धारित अवधि में बदलने की प्रक्रिया प्रभावी बनाने के लिये एक नई योजना ''एसएमएस आधारित असफल ट्रांसफार्मर बदलना, वितरण कम्पनियों द्वारा लागू की गई है। इसमें प्रत्येक ट्रांसफार्मर को यूनिक आईडी आवंटित कर ट्रांसफार्मर डीपी पर पेंट से लिखा गया है। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में किसान विद्युत उपभोक्ता निर्धारित मोबाइल नम्बर पर उस ट्रांसफार्मर का यूनिक आईडी कोड दर्शाते हुए एसएमएस भेज सकेगा। इसके मिलने पर सर्वर के माध्यम से यह सूचना संबंधित अधिकारी तथा शिकायतकर्ता उपभोक्ता को भी अग्रिम प्राप्त होती है। संबंधित अधिकारी द्वारा सूचना की जांच कर ट्रांसफार्मर बदलने के लिये अयोग्य अथवा योग्य पाये जाने की जानकारी सर्वर को भेजी जाती है। इसके आधार पर ट्रांसफार्मर बदलने की वरीयता सूची स्वतः जनरेट होती है, जिसे कम्पनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ट्रांसफार्मर बदलने के बाद इसकी सूचना उपभोक्ता को भी स्वतः एसएमएस के जरिये मिलती है। यह व्यवस्था वर्ष 2012 के रबी मौसम से लागू किये जाने के फलस्वरूप जलेध्खराब ट्रांसफार्मर बदलने की अवधि में कमी आई है।

किसानों को मिलेगी पल-पल की जानकारी

प्रत्येक कृषक का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा जिसमें उनकी मूलभूत जानकारी के साथ उनके मोबाइल नंबर भी प्राप्त किये जायेंगे। कृषि की अद्यतन जानकारी एवं सामयिक सलाह एसएमएस के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करवायी जायेगी। कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों को नई किस्म के बीज तैयार करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली कोदो, कुटकी, रामतिल जैसी फसलों के बीज उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा प्रसंस्करण के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जायेंगे। इससे प्रदेश के कृषक इन फसलों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें एवं उनकी खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा लाभ किसान भाइयों को मंडी प्रांगण में उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से दिसम्बर 2014 तक प्रदेश के सभी मुख्य कृषि उपज मंडी प्रांगणों में एमपी आनलाइन के कियोक्स स्थापित किये गए हैं। इससे किसान भाई ई.उपाजऱ्न की जानकारी, बही की नकल का प्रिन्ट आउट अन्य शासकीय योजनाओं की जानकारी आदि सुगमता से प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के किसान को मंडी की आवक एवं भाव की सतत जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किसान भाइयों को तथा सभी उपयोगकताओंजं को प्रदेश की मंडी समिति में अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराने पर प्रतिदिन निःशुल्क एसएमएस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

चौथी दुनिया इफ़्तार पार्टी

1

2

3

4

5

चौथी दुनिया इफ़्तार पार्टी

1. राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र चौथी दुनिया द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इफ्तार पार्टी में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का स्वागत करते हुए कमल मोरारका और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय. 2. कमल मोरारका के साथ अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम अब्दुल बारी चिश्ती. 3. केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और फिल्म पटकथा लेखक, अभिनेता एवं निर्देशक रूमी जाफरी और उनकी पत्नी के साथ चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय 4. वरिष्ठ वकील एवं सांसद माजिद मेमन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू के साथ कमल मोरारका 5. साफा पहने कमल मोरारका 6. दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता हारुन युसूफ के साथ कमल मोरारका 7. कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल के साथ कमल मोरारका और चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय 8. भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जोशी के साथ चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय 9. इफ्तार में आए मेहमानों का स्वागत करते कमल मोरारका और संतोष भारतीय 10. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के साथ बातचीत करते संतोष भारतीय 11. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर से बातचीत करते कमल मोरारका 12. भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से बातचीत करते कांग्रेस नेता राशिद अल्वी 13. कमल मोरारका के साथ गोपी मनचंदा व पूर्व सांसद सोमपाल 14. संतोष भारतीय से हाथ मिलाते मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 15. भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद पुतुल कुमारी से बातचीत करते कमल मोरारका 16. संतोष भारतीय के साथ फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद 17. फिल्मकार मुजफ्फर अली के साथ कमल मोरारका व अन्य 18. कमल मोरारका को गुलदस्ता देते हुए ईटीवी के एडिटर-इन-चीफ जगदीश चंद्रा 19. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पूनिया से मिलते हुए संतोष भारतीय 20. भाजपा नेता अशोक प्रधान के साथ संतोष भारतीय 21. केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ संतोष भारतीय एवं अन्य अतिथिगण 22. फिल्मकार मुजफ्फर अली से बातचीत करती हुई फिल्म निर्देशक फौजिया अर्शी एवं साथ में रीना भारतीय 23. कमल मोरारका से बातचीत करते तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भीष्म नारायण सिंह

(संबंधित फोटो पेज 14 पर भी देखें)

सभी फोटो-**प्रभात पाण्डेय**

6

7

8

9

10

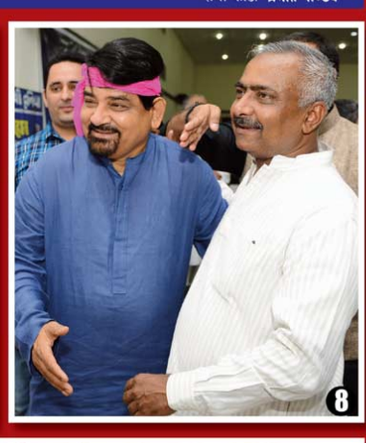

11

12

13

14

15

16

17

18

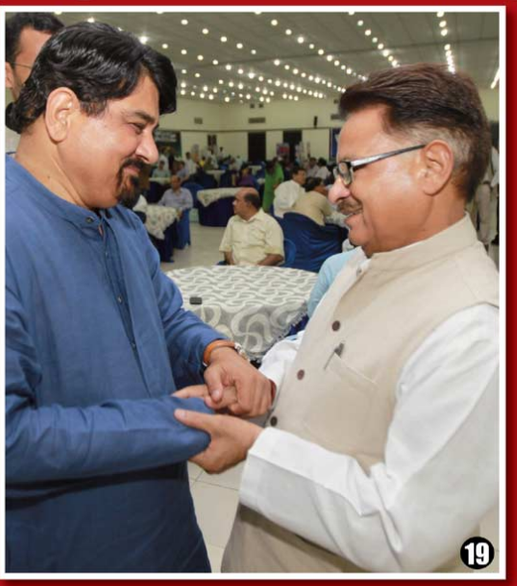
19

20

21

22

23

साहित्य के पाठकों की कमी नहीं

अनंत विजय

इन दिनों देशभर में सेल का मौसम चल रहा है और हर अखबार सेल-सेल-सेल के तरह तरह के विज्ञापनों से अटा पड़ा है. विक्रेता तरह-तरह से क्रेता को लुभाने में लगे हैं, कोई पचास फीसदी कम मूल्य पर तो कोई अमुक प्रोडक्ट के साथ अमुक चीज मुफ्त देने के वादे के ऑफर दिए जा रहे हैं. कपड़ों से लेकर हवाई जहाज के टिकटों तक की सेल चल रही है. इन प्रोडक्ट्स के जबरदस्त विज्ञापनों के कोलाहल के बीच एक अलग तरह के सेल की खबर दब सी गई. चौबीस पचीस जून को दो दिनों के लिए अंग्रेजी के प्रकाशक हॉर्पर कॉलिंस ने फरीदाबाद के अपने गोदाम में किताबों की सेल लगाई थी. इस सेल का न तो किसी अखबार में बड़ा-बड़ा विज्ञापन दिया गया था न ही टीवी पर, लेकिन खरीदारों की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. लोग सेल शुरू होने के वक्त से पहले फरीदाबाद के गोदाम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे. भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि प्रकाशक को गेट बंद करना पड़ा और ट्विटर पर ये जानकारी देनी पड़ी कि स्टॉक खत्म हो गए हैं. सेल लगाने वाले प्रकाशक ने दिल्ली वालों का धन्यवाद भी अदा किया. दरअसल हॉर्पर कॉलिंस ने सोशल मीडिया आदि पर एलान किया था कि दो दिनों के लिए वो अपनी किताबों की सेल लगा रहे हैं जहां कि पच्चीस रुपये से लेकर सौ रुपये तक में किताबें मिलेंगी. इसके अलावा एक दो अखबारों में सेल के बारे में छोटी सी खबर छपी थी. प्रकाशक ने पुस्तक प्रेमियों को अपने गोदाम पर आने का न्यौता दिया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाशक को इस बात का अंदाज नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में और इतनी भयंकर गर्मी में पुस्तक प्रेमी वहां तक पहुंच जाएंगे. खैर काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों को किताबें मिली तो कइयों को निराश होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा. जो लोग निराश होकर लौटे उन्होंने अपनी निराशा ट्विटर के जरिए जाहिर की. हॉर्पर कॉलिंस हैशटैग के साथ ट्विटर पर लोगों ने अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी. कई लोगों ने तो लिखा कि वो सुबह से गोदाम के खुलने की प्रतीक्षा करते रहे लेकिन जब उनका नंबर आया तो प्रकाशक ने गेट बंद कर दिया. इस तरह के दर्जनों ट्वीट्स दो दिनों के दौरान देखे गए. दिल्ली के गुस्से में होने की वजह से कुछ समय के लिए हॉर्पर कॉलिंस ट्विटर पर ट्वीट भी करने लगा था.

अब इस पूरी घटना से पुस्तकों की बिक्री को लेकर कई मिथक टूटते हैं. हमारे देश में खासकर हिंदी में पुस्तकों की बिक्री को लेकर प्रकाशकों और लेखकों दोनों में कोई उत्साह देखने को नहीं मिलता है. एकाध प्रकाशक को छोड़ दें तो पाठकों तक पहुंचने की योजना और उसका कार्यान्वयन दिखाई नहीं देता है. पुस्तक मेलों को छोड़ दें तो किसी भी हिंदी के प्रकाशक ने कभी पुस्तकों की सेल लगाई हो ऐसा याद नहीं पड़ता है. पुस्तकों की सेल तो एक उदाहरण है. इस तरह के कई उपक्रम किए जा सकते हैं ताकि पुस्तकों को पाठकों तक पहुंचाया जा सके. इसके लिए प्रकाशकों को पहल करनी चाहिए और लेखकों को उनका सहयोग और सपोर्ट दोनों करना चाहिए. हॉर्पर कॉलिंस की बुक सेल ने यह तो साबित कर ही दिया कि पुस्तकों की खरीद के लिए पुस्तक प्रेमी अपना वक्त और धन दोनों खर्च करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि किताबें कम मूल्य पर मिले और निश्चित स्थान पर उपलब्ध हों. हिंदी में किताबों की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है. आज दिल्ली का ही उदाहरण लें और सर्वे करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस महानगर में दर्जन भर से ज्यादा किताबों की दुकानें नहीं होगीं. हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित पुस्तक केंद्र पर ही मिल पाती हैं. इसी तरह से लखनऊ और पटना में भी देखें तो तीन चार ही किताबों की दुकानें मिलेंगी. कई छोटे शहरों में तो वहां के रेलवे स्टेशन पर मौजूद एच एच व्हीलर के स्टॉल ही उस शहर के साहित्यप्रेमियों का अड्डा हुआ करता है. अफसोस कि वहां भी स्टॉल मालिक के व्यक्तिगत प्रयास से साहित्यक पत्र-पत्रिकाएं तो उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन साहित्यक कृतियां मसलन कहानी संग्रह और उपन्यास आदि तो नहीं ही मिल पाती हैं.

हिंदी पट्टी में आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में उमड़ी भीड़ भी हमेशा ये संदेश देती है कि किताबों के पाठक हैं. उनको सहजता से उपलब्ध करवाने की जरूरत है. इस साल नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में हिंदी के हॉल के बाहर पुस्तक प्रेमी कतार लगाकर किताबें खरीदने के लिए जा रहे थे. इसी तरह से

पटना और लखनऊ के पुस्तक मेलों में भी पाठकों की उमड़ी भीड़ बेहद उत्साहजनक संकेत देते हैं. अब तो छोटे-छोटे शहरों में पुस्तक मेले लगने लगे हैं और आयोजकों समेत प्रकाशकों की उसमें हिस्सेदारी होती है. मैं यह नहीं कह सकता हूं कि प्रकाशकों को इन छोटे पुस्तक मेलों में मुनाफा होता है या नहीं लेकिन उनकी लगातार उपस्थिति से इतना तो कहा जा सकता है कि प्रकाशकों को घाटा नहीं होता है. तो फिर क्यों नहीं इस काम को सुनियोजित तरीके से किया जाता है? प्रकाशकों के कई संगठन हैं उनको इस काम में आगे आना चाहिए लेकिन प्रकाशकों के संगठनों का हाल भी लेखक संगठनों से बेहतर नहीं है. सबके अपने अपने राम हैं.

इसी तरह से नेशनल बुक ट्रस्ट पर भी देशभर में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने और परोक्ष रूप से किताबों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है. इस बात का आकलन किया जाना चाहिए कि क्या नेशनल बुक ट्रस्ट अपनी इन जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है. अभी पिछले साल तो एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट पटना पुस्तक मेले के आयोजकों से होड़ लेता नजर आया. दशकों से पटना पुस्तक मेला आयोजित होता है और तमाम झंझावातों को झेलते हुए उसने बिहार और देश के साहित्यिक कैलेंडर में अपना स्थान बनाया. पटना पुस्तक मेले के आयोजन के ठीक पहले नेशनल बुक ट्रस्ट ने भी पटना के गांधी मैदान में ही पुस्तक मेला आयोजित कर दिया. ट्रस्ट की मंशा का तो पता नहीं लेकिन एक ही वक्त और एक ही स्थान पर आयोजित होने से पाठकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहती है. नेशनल बुक ट्रस्ट को देश के उन हिस्सों में पुस्तक मेले आयोजित करने चाहिए जहां तक पहुंचना मुश्किल है. हवाई रूट से जुड़े शहरों में नेशनल बुक ट्रस्ट के मेलों में उनके अफसरों को जाने में सहूलियतें होती हैं लेकिन इससे पुस्तक संस्कृति का अपेक्षित विस्तार हो पाता है, इसमें संदेह है. नेशनल बुक ट्रस्ट को किताबों को छापने से ज्यादा ध्यान किताबों की उपलब्धता पर लगाना चाहिए. उनको प्रकाशकों के साथ साझेदारी कर किताबें छपवानी चाहिए और मूल्य और गुणवत्ता निर्धारण के मानदंड तैयार करना चाहिए. जैसे ही वो किताबें छापते हैं तो वो अन्य प्रकाशकों से होड़ लेने लगते हैं. ट्रस्ट के पास चूंकि सरकारी पैसा है लिहाजा वो प्रकाशकों की निजी पूंजी पर भारी पड़ते हैं और परोक्ष रूप से पुस्तक संस्कृति के विकास को नुकसान पहुंचाते हैं. इसी तरह से साहित्य अकादमी को भी किताबों के प्रकाशन पर अपनी ऊर्जा और धन खर्च करने से ज्यादा जरूरी है कि वो किताबों के प्रचार प्रसार के लिए काम करे. बेहतर लेखकों का चयन करे और उनकी किताबों को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने के लिए प्रकाशकों के साथ साझेदारी करे. स्तरीय अनुवाद करवाकर प्रकाशकों को उपलब्ध करवाए. जब वो खुद इस काम में लगते हैं तो देर भी होती है जैसे भारत भारद्वाज ने डी एस राव की किताब फाइव डिकेड्स का अकादमी के लिए अनुवाद किया था लेकिन उसका प्रकाशन छह सात साल बाद हो पाया. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई, लेकिन संभव है कि ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हों. सरकारी पूंजी से किताबों का प्रकाशन करने वाली संस्थाओं को लागत की फिक्र नहीं होती है. इस तरह की अड़चनों की अगर चूलें कस दी जाएं तो पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ सकती है और पाठकों की मौजूदगी से इस इंडस्ट्री को मुनाफा हो सकता है. किसी भी सेक्टर के विकास के उसमें मुनाफा होना आवश्यक है. इसके अलावा अगर लेखक भी अपनी किताब की उपलब्धता को लेकर प्रकाशक के कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो स्थिति और बेहतर हो सकती है. सामूहिक प्रयास से ही बेहतर पुस्तक संस्कृति का विकास संभव है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.tbn@gmail.com

1

2

3

4

5

6

7

चौथी दुनिया इफ़्तार पार्टी

1- चौथी दुनिया द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी के मौके पर किसान मंच की तरफ से भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को सम्मानित करते कमल मोरारका. 2- किसान मंच की तरफ से केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को सम्मानित करते चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय एवं अन्य. 3- किसान मंच की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैय्यर को सम्मानित करते चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय. 4-किसान मंच की तरफ से प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज को सम्मानित किया गया. 5-किसान मंच की तरफ से फिल्म पटकथा लेखक, अभिनेता एवं निर्देशक रूमी जाफरी को सम्मानित करते हुए चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय. 6-क्रिश्चियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जॉन दयाल का स्वागत करते संतोष भारतीय. 7- मौलाना तौकीर रजा खान को किसान मंच की ओर से सम्मानित करते हुए संतोष भारतीय. 8- सरदार गुरदीप सिंह को सम्मानित करते हुए किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सिंह. 9- यूनाइटेड अकाली दल के अध्यक्ष भाई मोहकम सिंह को किसान मंच की ओर से सम्मानित करते संतोष भारतीय

8

9

खिलाड़ियों में बढ़ती डोपिंग

विश्व खेल पटल पर डोपिंग का खेल भी खूब फल-फूल रहा है. खिलाड़ी आए दिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबन्धित दवाएं धड़ल्ले से सेवन करते हैं. हाल के दिनों में डोपिंग की घटनाएं लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं. अभी कुछ ही दिन पहले रूसी एथलेटिक्स टीम को ओलम्पिक से आउट इसलिए कर दिया गया कि उसके खिलाड़ी डोपिंग में लिप्त पाए गए थे. खेलों की दुनिया में खिलाड़ी कामयाबी की दास्तान लिखते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का दूसरा हिस्सा बड़ा कड़वा होता है.

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

रियो ओलम्पिक की उलटी गिनती शुरू हो गई है. विश्व के कद्दावर खिलाड़ी ओलम्पिक में पदक जीतने का सपना देख रहे हैं. दुनिया के कई देश के खिलाड़ी ओलम्पिक को ध्यान में रखकर पसीना बहाते हैं लेकिन इनमें से कुछ खिलाड़ी पदक की चाह में गलत कदम भी उठा लेते हैं. ऐसे खिलाड़ी अपने देश को शर्मसार करते हैं. दरअसल विश्व खेल पटल पर डोपिंग का खेल भी खूब फल-फूल रहा है. खिलाड़ी आए दिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रतिबन्धित दवाएं धड़ल्ले से सेवन करते हैं. हाल के दिनों में डोपिंग की घटना लगातार सुर्खियों में बनी रही है. अभी कुछ ही दिन पहले रूसी एथलेटिक्स टीम को ओलम्पिक से आउट इसलिए कर दिया गया कि क्योंकि उसके खिलाड़ी डोपिंग में लिप्त पाए गए थे. खेलों की दुनिया में अक्सर खिलाड़ी कामयाबी की दास्तान लिखता है, लेकिन उसकी कामयाबी का दूसरा हिस्सा बड़ा कड़वा होता है. वह नाम कमाने के लिए खेल से गहारी करने को उतारू हो जाते हैं. मरियन जोन्स से लेकर मारिया शारापोवा जैसे खिलाड़ियों तक ने अपने प्रदर्शन के बल पर लोगों का दिल जीता है. लेकिन बाद में इनकी असलियत खुली तो पूरे खेल जगत में हड़कम्प मच गया. वह भी ऐसे वक्त जब ओलम्पिक में बेहद कम दिन रह गए हैं. ताजा मामलों में रूसी खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता रहा. इस घटना के बाद खिलाड़ी अर्श से फर्श पर आ जाता है. उसकी तमाम उपलब्धि एक झटके में बेकार हो जाती है. डोपिंग का मामला कोई नया नहीं है. अतीत में भी कई खिलाड़ी डोपिंग के खेल में रंगे हाथ पकड़े गए हैं. मौजूदा समय में डोपिंग को लेकर इतनी धर पकड़ केवल ओलम्पिक की वजह से हो रही है.

डोपिंग को लेकर आए दिन खुलासे हो रहे हैं. सारा मामला 2014 में रूस के सोच्चि में आयोजित हुए शीतकालीन ओलम्पिक खेलों को लेकर है. माना जा रहा है कि इस शीतकालीन ओलम्पिक खेलों के खिलाड़ियों ने पदक जीतने के लिए जमकर स्टेरॉयड का सेवन किया था. इतना ही नहीं चार रूसी खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक पर कब्जा भी किया था, लेकिन यह चारों स्टेरॉयड लेने के दोषी बताए जा रहे हैं. यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है. व्हिसिल-ब्लोअर विताली स्तेपानोव की मानें तो उनके पास रूस की दवाई परीक्षण लैब प्रमुख के टेप हैं. इस टेप में खिलाड़ियों ने स्टेरॉयड का सेवन करने की बात मानी है. स्तेपानोव रूस की डोपिंग रोधी एजेंसी के सदस्य भी रह चुके हैं. इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ ऐसे एथलीट आपको मिलेंगे जो शीर्ष पर होने के बावजूद डोपिंग के डंक ने उनके करियर को चौपट कर दिया था. यह बात सत्य है कि अक्सर खिलाड़ी अंजाने में किसी भी प्रतिबन्धित दवा का सेवन कर डालते हैं. चोट से उबरने के लिए ऐसा हो जाता है. अमेरिका की स्टार एथलीट मरियन जोन्स की बात की जाए तो उनका करियर बुलन्दियों पर रहकर अचानक जमीन पर आ गया था. मरियन जोन्स ने ओलम्पिक में तीन स्वर्ण जीतकर ट्रैक फील्ड की दुनिया में बेताज बादशाह बन गई थीं, लेकिन अचानक उनका नाम डोपिंग में शामिल हो गया था. कई रिकॉर्डों की झड़ी लगाने वाली जोन्स को वर्ष 2007 में अयोग्य ठहरा दिया गया था. इसके बाद उनके सारे मेडल छीन लिए गए थे. इतना ही नहीं उन्हें छह महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ी थी.

विताली स्तेपानोव

प्रियंका पवार

इसके बाद तो खेलों की दुनिया में डोपिंग को लेकर कई खिलाड़ियों के नामों का खुलासा होने लगा. कुछ ऐसे भी थे जिनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता था. बेन जॉनसन को उस जमाने में सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन उनका प्रदर्शन डोप के डंक से अछूता नहीं रहा. वर्ष 1988 में सिओल ओलम्पिक में सबसे तेज दौड़ते हुए स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था. इतना ही नहीं, वे विश्व के सबसे तेज धावक के रूप में जाने जाते थे. उनके चमकदार करियर पर तब कालिख पुत गई जब एक टीवी कार्यक्रम के दौरान बेन जॉनसन ने यह कबूल कर लिया था कि वह खेल से गहारी करते हुए डोपिंग में शामिल थे. उनका यह काला सच जब दुनिया के सामने आया तो खेल प्रेमी एक दम से चौंक गए. बाद में उनके सारे रिकॉर्ड छीन लिए गए और उनपर प्रतिबन्ध भी लगाया गया था. अमेरिका के स्टार साइकिलिंग खिलाड़ी और सात बार के फ्रांस द टूर विजेता लांस आर्मस्ट्रांग को पूरी दुनिया जानती है. वह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लम्बे समय तक जूझते रहे. दुनिया उनके इस जज्बे को सलाम करती है. लांस आर्मस्ट्रांग ने अपने साइकिलिंग करियर में खूब नाम कमाया. उनका प्रदर्शन बेजोड़ था, लेकिन डोपिंग का भी उनको खूब साथ मिला था. आर्मस्ट्रांग ने खुद डोपिंग की बात मानी थी. इसके बाद उनके सारे खिताब छिन लिए गए थे. हाल के दिनों में टायसन गे भी डोपिंग के फंदे में फंस चुके हैं. वर्ष 2013 में उनके भी प्रतिबन्धित स्टेरॉयड लेने की बात सामने आई. इसके बाद उनपर एक साल का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था. इतना ही नहीं, लंदन ओलम्पिक का पदक भी उनसे छिन लिया गया था. बात अगर ताजा उदाहरण की जाए तो इसमें सबसे पहले मारिया शारापोवा का नाम आता है. एक वक्त ऐसा था जब टेनिस जगत में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी मारिया शारापोवा की न सिर्फ खेल की तारीफ होती थी बल्कि उनकी खूबसूरती भी चर्चा में रहती थी, जो उनके खेल को चार-चांद लगाती थी. लेकिन जबसे रूसी सुन्दरी का नाम डोपिंग में शामिल हुआ, तब से उनका कद गिरता जा रहा है. इसके बाद मारिया शारापोवा ने आनन फानन में सफाई देते हुए कहा कि डायबिटीज की वजह से वे मेलिडोनियम नामक ड्रग्स का सेवन करती हैं लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेन्सी वाडा की लिस्ट में वह प्रतिबन्धित दवा में शुमार है. उनको उम्मीद है कि उनका करियर खत्म होने से बच जाएगा. ऐसा नहीं है कि विदेशी खिलाड़ी ही डोपिंग का शिकार हुए हैं. भारतीय खिलाड़ी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं. डोपिंग के छींटे अश्वनी अंकुजी, मनदीप कौर और सिन जोस जैसे बड़े एथलीटों पर पड़े हैं. एशियाड में दोहरी सफलता हासिल करने वाली अश्वनी अंकुजी को स्टेरॉयड लेने का दोषी पाया गया था. इतना ही नहीं, देश की जानी मानी एथलीट प्रिंयका पवार, मैरी थामस और हरिकृष्णन पर भी डोपिंग के आरोप में प्रतिबन्ध लगा दिया गया था. खिलाड़ी अक्सर अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए हारमोंस तथा फुड सप्लिमेंट का प्रयोग करते हैं. बाद में यही डोपिंग के रूप में सामने आ जाता है. सवाल यह है कि डोपिंग के इस गंदे चक्रव्यूह से रियो ओलम्पिक को कैसे बचाया जाए. रियो ओलम्पिक में अब बेहद कम दिन रह गए हैं. ऐसे में आयोजकों के तेवर बता रहे हैं कि खेल को पाक साफ रखने के लिए वे किसी भी कड़ी कार्रवाई से परहेज नहीं करेंगे. एक रिपोर्ट के अनुसार खेल को दागदार करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 में 96 खिलाड़ी डोपिंग के दोषी पाए गए थे. ■

मारिया शारापोवा

टीम इंडिया को मिला 'जम्बो' कोच

टीम इंडिया की कोचिंग को लेकर चल रही माथापच्ची आखिरकार अनिल कुंबले के नाम पर खत्म हो गई. पिछले एक महीने से टीम इंडिया के नए कोच की तलाश चल रही थी. बीसीसीआई ने इस बार नए कोच के लिए काफी मेहनत की थी. 2015 में डंकन फ्लेचर के जाने के बाद से टीम इंडिया के कोच का पद खाली था. इस दौरान अस्थायी तौर पर रवि शास्त्री किसी न किसी रूप में यह जिम्मेदारी निभाते रहे थे. दरअसल विदेशी और देसी कोच को लेकर इस बार बोर्ड बेहद गंभीर दिखा. कोच नियुक्त करने से पहले बीसीसीआई ने विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद 57 आवेदकों को इसमें जगह मिली थी. बोर्ड ने इसके लिए सलाहकार समिति बनाई थी. इस समिति में सचिन, सौरभ व लक्ष्मण जैसे कई बड़े पूर्व क्रिकेटर शामिल थे. टीम इंडिया का कोच बनने की दौड़ में कई दिग्गज क्रिकेटर लाइन में थे, लेकिन कुंबले के स्पिन के आगे कई नामी गिरामी क्रिकेटरों की नहीं चली. अनिल कुंबले ने रवि शास्त्री व संदीप पाटिल जैसे खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए टीम इंडिया का कोच बनने का गौरव हासिल किया. यह इसलिए अहम है, क्योंकि 16 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी को टीम इंडिया का कोच बनने का मौका मिला है. 16 साल पहले कपिल देव को भारतीय टीम का कोच बनाया गया था. कपिल के बाद टीम इंडिया ने विदेशी कोच पर भरोसा किया. लेकिन भारत में कोचिंग को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है. विदेशी कोच पर कई बार सवाल भी उठाए जा चुके हैं.

1992 से टीम इंडिया में कोच रखने की प्रथा शुरू हुई. भारत के पहले कोच के रूप में अजित वाडेकर को चुना गया था. वह 1996 तक टीम इंडिया के कोच रहे. इसके बाद संदीप पाटिल, मदन लाल, अंशुमन गायकवाड़ और कपिल देव जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी जिम्मेदारी निभाई. साल 2000 में जॉन राइट के रूप में भारत को पहला विदेशी कोच मिला. यह वह दौर जब टीम इंडिया की कमान सौरभ गांगुली के हाथ में थी. दादा और जॉन राइट की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. दोनों की शानदार जुगलबंदी से टीम इंडिया ने कई खिताब अपने नाम किए.

1992 से टीम इंडिया में कोच रखने की प्रथा शुरू हुई. भारत के पहले कोच के रूप में अजित वाडेकर को चुना गया था. वह 1996 तक टीम इंडिया के कोच रहे. इसके बाद संदीप पाटिल, मदन लाल, अंशुमन गायकवाड़ और कपिल देव जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने इसकी जिम्मेदारी निभाई. साल 2000 में जॉन राइट के रूप में भारत को पहला विदेशी कोच मिला. यह वह दौर जब टीम इंडिया की कमान सौरभ गांगुली के हाथ में थी. दादा और जॉन राइट की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. दोनों की शानदार जुगलबंदी से टीम इंडिया ने कई खिताब अपने नाम किए. उनके कोच बनते ही वीरू से लेकर कैफ तक खूब चमके. जॉन राइड के बाद से भारत लगातार विदेशी कोच की सेवाएं ले रहा है. इस दौरान कोच को लेकर काफी किच-किच देखने को मिली. ग्रेग चैपल के कोच बनते ही टीम इंडिया में दरार आ गई थी. चैपल अपने फायदे के लिए टीम इंडिया को चला रहे थे. चैपल और दादा के बीच काफी मतभेद उभरकर सामने आया था. खैर इसके बाद गैरी कर्सटन के कार्यकाल में टीम इंडिया के प्रदर्शन में काफी सुधार आया.

कुल मिलाकर यह देखना रोचक होगा कि कोच जम्बो टीम इंडिया को कहां पहुंचाते हैं. जम्बो को ऐसे वक्त में टीम इंडिया को कोच बनने का अवसर मिला है जब धोनी व विराट के बीच कप्तानी को लेकर खिंचातानी चल रही है. मौजूदा दौर में अनिल कुंबले का हर कोई सम्मान करता है. खुद विराट कोहली ने अनिल कुंबले की तारीफ की है. अनिल कुंबले जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में जम्बो कहते हैं, के प्रशिक्षण में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है, इसका लोगों को इंतजार है. ■

feedback@chauthiduniya.com

फ्लैशबैक

जब मंदाकिनी की खूबसूरती पर डॉन का दिल आया

बेहद खूबसूरत दिखने वाली मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963, में एक एंग्लो-इंडियन (इंग्लैंड-भारतीय) परिवार में हुआ था. उनका नाम यासमीन जोसफ था. उनके पिता जोसफ एक ब्रिटिश नागरिक हैं और माता भारतीय मुस्लिम हैं. मंदाकिनी सुपरहिट फिल्म *राम तेरी गंगा मैली* में अपनी श्रेष्ठ भूमिका के लिए जानी जाती हैं.1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में एक ऐसी एक्ट्रेस ने कदम रखा था, जो आज भी फिल्म *राम तेरी गंगा मैली* से लोगों के बीच में पहचान बनाए हुए है. कहने को यह बात 29 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का चेहरा आज भी दर्शक भूला नहीं पाए हैं. मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1985 में की थी. उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बंगाली फिल्म *अंतारेर भालोबाशा* से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म *मेरा साथी* के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा था. 1985 में उन्होंने दो फिल्में *आर-पार* और *राम तेरी गंगा मैली* की. राज कपूर के डायरेक्शन में बनी *राम तेरी गंगा मैली* बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को नया मुकाम दिया और उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. बॉलीवुड में मंदाकिनी की जीवन-यात्रा अत्यंत छोटी रही. फिल्म *राम तेरी गंगा मैली* में मंदाकिनी के कुछ विवादस्पद दृश्य फिल्माए गए थे. इन आपत्तिजनक दृश्यों के बावजूद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी और फिल्म सुपरहिट हुई. मंदाकिनी को इस नमांकित किया गया था.

उसके बाद मंदाकिनी ने फिल्म *डांस-डांस, लोहा, प्यार करके देखो, शेषनाग, नाग-नागिन, जोरदार* आदि फिल्मों में अभिनय किया और सफलता की ओर आगे बढ़ती रहीं. मंदाकिनी को बोल्ड सीन्स देने से परहेज नहीं था. शायद यही वज़ह रही कि उनका फिल्मी करियर रफ्तार के साथ आगे बढ़ा.1985 में मेरा साथी से शुरू हुआ मंदाकिनी का करियर 1996 में फिल्म *जोरदार* के साथ समाप्त हो गया. फिल्मों से संन्यास लेने के दो साल पहले यानी 1994 में मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा. कहा जाता है कि दाउद मंदाकिनी की खूबसूरती का दीवाना था. शारजाह के मैच में मंदाकिनी के साथ दाऊद की तस्वीर ही काफी थी डॉन के साथ उनकी नजदीकियों का बताने के लिए. 80 के दशक में दर्शकों के दिल पर राज करने वाली मंदाकिनी इन दिनों तिब्बतन योगा की क्लासेस चलाती हैं और वो दलाई लामा की फॉलोअर हैं.■

कामयाबी हमेशा के लिए नहीं होती प्रियंका

2012 में अपने एकल गीत इन माई सिटी से पश्चिम में अपने करियर की शुरुआत करने वाली 33 वर्षीय अभिनेत्री बाद में अमेरिकी टीवी धारावाहिक क्वांटिको में मुख्य भूमिका में नज़र आई थीं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हॉलीवुड में बेवॉच फिल्म साइन की. अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आईफा) समारोह में प्रियंका ने कहा, मेरा मानना है कि आप जो हैं वही रहें. मैं सफलता को स्थाई मान कर नहीं चलती और किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए.

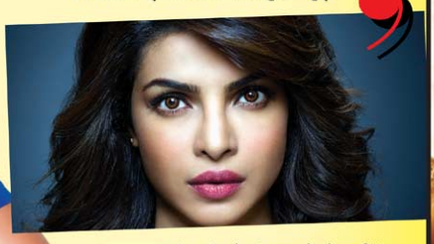

ब्यूटी क्वीन के खिताब से लेकर हिंदी फिल्म जगत की स्टार और अंतरराष्ट्रीय गायिका बनने और अब हॉलीवुड की अभिनेत्री बनने तक का प्रियंका चोपड़ा का सफर सफलता की नई कहानी कहता है, लेकिन यह बात उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है. उनका कहना है सारी शोहरत और शान एक दिन चली जाएगी.

2012 में अपने एकल गीत *इन माई सिटी* से पश्चिम में अपने करियर की शुरुआत करने वाली 33 वर्षीय अभिनेत्री बाद में अमेरिकी टीवी धारावाहिक क्वांटिको में मुख्य भूमिका में नज़र आई थीं. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और हॉलीवुड की बेवॉच फिल्म साइन की. अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (आईफा) समारोह में प्रियंका ने कहा, मेरा मानना है कि आप जो हैं वही रहें. मैं सफलता को स्थाई मान कर नहीं चलती और किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए. पलक झपकते सफलता गायब हो जाएगी. मुझे यकीन है कि एक दिन यह मेरे पास से भी चली जाएगी, लेकिन मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, इसलिए आपको अलग-अलग चीजों में सक्षम बनना होगा.

प्रियंका ने कहा कि आज समय बदल गया है और उन लोगों के लिए ढेर सारे अवसर हैं जो इसे दोनों हाथों से लपकने के लिए तैयार हैं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड का सुल्तान सलमान खान

सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सलमान खान की झोली में एक और ब्लॉक-बस्टर फिल्म डाल दी. सुल्तान के साथ ही सलमान ने लगातार 10वीं हिट फिल्म दी है. उम्मीद है कि फिल्म सुल्तान सलमान के करियर की बड़ी हिट फिल्म होगी.

प्रवीण कुमार

सलमान खान इस साल बॉलीवुड में 27 साल पूरे कर रहे हैं और सलमान खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में 27 साल गुजार लिए. सलमान खान ने फिल्म *बीवी हो तो ऐसी* (1988) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस मौके पर सलमान खान ने कहा कि-पता भी नहीं चला कि फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल कैसे निकल गए. मैं बहुत खुश हूं, जिस तरह मुझे सफलता मिली है... मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी दूर आ पाऊंगा. मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे कहां ले जाएगी, लेकिन सब अच्छा रहा और मुझे किसी चीज की शिकायत नहीं है.

फिलहाल सलमान खान काफी समय से फिल्म सुल्तान में व्यस्त थे. जो ईद के मौके पर रिलीज़ हो चुकी है. कोई शक नहीं कि सलमान खान की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी. सलमान को उम्मीद है की उनकी फिल्म *सुल्तान* इस साल कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है. रिलीज़ के बाद *सुल्तान* ने धमाकेदार शुरूआत की है. ईद पर *सुल्तान* को रिलीज़ करने का फायदा सलमान को मिला और फिल्म ने बंपर ओपनिंग की है. एक रिपोर्ट की मुताबिक, यशराज फिल्म्स के हेड (मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका) ने कहा है कि *सुल्तान* को यूएई में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

यशराज फिल्म्स के प्रवक्ता ने कहा-शाहरुख खान की फैन को यूएई के 95 लोकेशन पर रिलीज़ किया गया था. जबकि सुल्तान को 99 लोकेशन पर किया गया है. यहां तक की मिडिल ईस्ट में सुल्तान का प्रमोशन भी जोरशोर के साथ किया गया. यूं तो सलमान एक-एक करके बॉलीवुड के कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बनना है तो *सुल्तान* के सामने इस साल कई आंकड़े हैं, जिसे सलमान खान को पार करना है.

सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सलमान खान की झोली में एक और ब्लॉक-बस्टर फिल्म डाल दी.

सुल्तान के साथ ही सलमान ने लगातार 10वीं हिट फिल्म दी है. उम्मीद है कि फिल्म *सुल्तान* सलमान के करियर की बड़ी हिट फिल्म होगी.

बहरहाल, खुशी और हैरानी की बात यह है कि दबंग के बाद सलमान की अब तक सारी ही फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश और विदेश में सलमान के फैंस की संख्या कितनी ज्यादा है.■

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान में बादशाहों

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज स्टारर फिल्म बादशाहों की शूटिंग जल्द ही राजस्थान में शुरू होगी. फिल्मकार मिलन लूथरिया ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि राजस्थान में दो महीने की शूटिंग का प्लान तैयार किया गया है.

राजस्थान के बाद फिल्म की बाकी की शूटिंग मुंबई में किए जाने की भी बात कही गई है. हालांकि इससे पहले फिल्म की अधिकांश शूटिंग पंजाब में किए जाने की चर्चा थी.

उल्लेखनीय है कि अपनी आगामी फिल्म बादशाहों के स्टार कास्ट का खुलासा करते हुए लूथरिया ने अजय देवगन और इलियाना के साथ इमरान हाशमी, विद्युत जामवाल और ईशा गुप्ता के चयन की बात कही है. इससे पहले इसमें अजय देवगन के सामने ऐश्वर्या राय या करीना कपूर को लेने की बात चल रही थी. लेकिन सारी अफवाहों को एक तरफ रखते हुए अजय के अपोजिट इलियाना डिक्रूज को साइन किया गया है.

कच्चे धागे, डर्टी पिक्चर और *वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई* जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले लूथरिया ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है. बता दें कि यह फिल्म लूथरिया और भूषण कुमार द्वारा सह-निर्मित है.

यह थ्रिलर 1975 के आपातकाल पर आधारित है. राजस्थान में दो महीने और मुंबई में 15 दिनों के कार्यक्रम के बाद अगस्त में इसकी शुरूआत होगी. लूथरिया बादशाहों के लिए विदेशी एक्शन निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं. इसमें दर्शकों को अंकित तिवारी द्वारा संगीतबद्ध राजस्थानी लोकगीत भी सुनाई देंगे.■